RNI No. DELMUL/2012/47011

04 अगस्त, 2026 मंगलवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 124

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को मिला टीम इंडिया में मौका 07

संक्षिप्त वार्ता

पीएम के न्योते के बाद बांग्लादेश में चिन्मय दास को मिली जमानत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

हालांकि, बांग्लादेश की ओर से अभी यह तय नहीं किया गया है कि तारिक रहमान इस सम्मेलन में भाग लेने भारत आएंगे या नहीं। इसी बीच ढाका से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है, जिसे भारत और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों में से दो मामलों में जमानत दे दी है। उनके वकील के अनुसार, जिन मामलों में राहत मिली है, उनमें हत्या की कोशिश, सरकारी कार्य में बाधा, तोड़फोड़ और अन्य आरोप शामिल हैं। दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए शेष दो मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।

दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व आप विधायक बाल्यान को बड़ा झटका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज हुई है। जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश सुनाया, जो बाल्यान के लिए बड़ा कानूनी झटका है।

यह मामला कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है। आप नेता बाल्यान पर आरोप है कि वे फरार गैंगस्टर सांगवान के सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ मुख्य सबूत बाल्यान और सांगवान के बीच कथित मोबाइल बातचीत की ऑडियो क्लिप है। बाल्यान को बीते साल दिसंबर में मामले में गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उन पर और कई अन्य लोगों पर चार्जशीट दाखिल की।

प्राचीन पृथ्वीनाथ मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गोंडा। रुपईडीह ब्लॉक के खरगुपुर स्थित प्राचीन पृथ्वीनाथ मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। रात एक बजे से ही भक्त कतारबद्ध होकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे। हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। मंदिर में सावन के दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को विशेष आस्था के चलते श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। दिनभर दर्शन-पूजन और जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। गोंडा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहां स्थापित शिवलिंग को महाभारत कालीन और एशिया के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में गिना जाता है।

पाकिस्तान ने भारत से सटी सीमा पर तैनात कीं 250 चीनी तोपें

इस्लामाबाद। मई 2025 में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत से लगती पूरी पूर्वी सीमा पर व्यापक तोपखाना तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान सेना भारत सीमा के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के विभिन्न सेक्टरों में चीन निर्मित 250 एसएच-15 ट्रक-माउंटेड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को व्यवस्थित रूप से तैनात कर रही है। भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों के बाद अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा उठाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत

घनश्याम सिंह ने भाजपा को 6,016 मतों से हराया

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पकड़ कायम रखते हुए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों के अंतर से पराजित कर सीट पर पार्टी का कब्जा बरकरार रखा।

वेब वार्ता, भोपाल

मतगणना के बाद घोषित परिणामों के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के आशुतोष तिवारी को 60,741 मत मिले। इस तरह कांग्रेस ने निर्णायक बढ़त के साथ जीत हासिल की और उपचुनाव में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी।

उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार दामोदर यादव तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 22,527 वोट प्राप्त हुए। चुनाव में उनकी मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय स्वरूप दिया, हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहा। दतिया सीट पर कांग्रेस की जीत को राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह परिणाम कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है, क्योंकि पार्टी ने न केवल अपनी सीट बचाई, बल्कि भाजपा की चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना किया। दूसरी ओर, भाजपा को इस सीट पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और पार्टी नेतृत्व के समर्थन में नारे लगाए। वहीं, भाजपा ने जनादेश का सम्मान करते हुए परिणाम स्वीकार किया।

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत

पटना। बिहार की बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,953 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर राजनीतिक हलकों में बड़ा संदेश दिया है। इस परिणाम के साथ बांकीपुर उपचुनाव का सबसे अहम मुकाबला जन सुराज के पक्ष में समाप्त हुआ।

30 जुलाई को हुए मतदान के बाद सोमवार को पटना के बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। शुरूआती दौर से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए रहे और अंतिम चरण तक उन्होंने अपनी बढ़त कायम रखी। भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में इस सीट पर जन सुराज की जीत को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिणाम ने राज्य की राजनीतिक तस्वीर में नए समीकरणों की संभावनाओं को जन्म दिया है। यह प्रशांत किशोर का पहला विधानसभा चुनाव था और उन्होंने अपनी चुनावी पारी जीत के साथ शुरू की। चुनाव परिणाम आने के बाद जन सुराज समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

पीएम मोदी ने प्रेरक सुभाषित साझा कर कहा-

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य और कर्म न छोड़ें

वेब वार्ता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक प्रेरक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए जीवन में धैर्य और कर्म के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य और सतत प्रयास से अनुकूल परिस्थितियां दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में संस्कृत श्लोक- त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि दैवे धैर्यात्कदाचित्स्थितिम ाप्नुयात्सः। याते समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति कर्म एव।। साझा किया। इसके साथ उन्होंने हिंदी में उसका भावार्थ बताते हुए कहा, भाग्य प्रतिकूल होने पर भी व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र के बीच जहाज टूट जाने पर भी एक कुशल नाविक हार नहीं मानता और जीवित रहने के लिए तैरने का प्रयास जारी रखता है, उसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर कर्म करते रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ समय से समय-समय पर संस्कृत सुभाषितों के माध्यम से सामाजिक और नैतिक संदेश साझा करते रहे हैं। इससे पहले 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गुरु के महत्व पर आधारित एक श्लोक साझा किया था। उन्होंने लिखा था कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा, सद्विचार और संस्कारों का भी संचार करते हैं।

गुरू के प्रमुख गुण बताया गया है

इस अवसर पर उन्होंने गुरु के छह स्वरूपों का उल्लेख करने वाला संस्कृत श्लोक भी साझा किया था, जिसमें प्रेरणा, मार्गदर्शन, शिक्षा और आत्मबोध को गुरु के प्रमुख गुण बताया गया है। इसके अलावा 28 जुलाई को प्रधानमंत्री ने प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के प्रति भारतीय परंपरा के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए एक अन्य संस्कृत सुभाषित साझा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में ही मानवता का कल्याण निहित है तथा धर्म, ऋतुओं और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन ही सुख, सुरक्षा और समृद्धि का आधार है।

उच्चतम न्यायालय में अब 38 न्यायाधीशः लोकसभा में विधेयक पारित

नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को पारित किया। यह विधेयक विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से पारित हुआ। सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद शुरू हुई, तब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर नारेबाजी कर रहे थे। पीठासीन सभापति के आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमा, जिसके चलते विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। इससे पहले, सदन ने राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को भी अस्वीकृत किया।

मिस्र में 5.4 तीव्रता का तीव्र भूकंप, कई देशों तक कांपी धरती

काहिरा। मिस्र में सोमवार तड़के आए एक शक्तिशाली भूकंप के झटकों से हड़कंप मच गया। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के अनुसार, भूकंप के यह झटके भारतीय समयानुसार सोमवार सुबह लगभग 3 बजे महसूस किए गए। अचानक धरती कांपने से मिस्र के कई प्रांतों में अफरा-तफरी मच गई और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए।

वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार, यह भूकंप जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका मुख्य केंद्र सूएज शहर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर बताया है। हालांकि, अलग-अलग वैश्विक निगरानी एजेंसियों ने इसके केंद्र की दूरी सूएज से 29 से 38 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम के आसपास दर्ज की है। भूकंप का असर केवल मिस्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका केंद्र सूएज के करीब होने के बावजूद झटके मध्य पूर्व के कई अन्य देशों में भी बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। मिस्र की राजधानी काहिरा और गीजा समेत देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और साइप्रस के कई इलाकों में भी लोगों को तुरंत ही तेज झटके महसूस हुए।

भूकंप की घटना के तुरंत बाद रेड क्रिसेंट की टीमों ने प्रभावित इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत कार्यों को सक्रिय कर दिया है। राहत की बात यह है कि भूकंप के कई घंटों के बाद भी मिस्र के प्रभावित क्षेत्रों से किसी भी तरह की जनहानि, गंभीर चोट या संपत्तियों के बड़े नुकसान की कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर पुरानी, जर्जर और क्षतिग्रस्त दिखने वाली इमारतों से लोगों को दूर रहने की सख्त सलाह दी है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने आम नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आह्वान किया है।

देश के कई राज्यों में बारिश से तबाही, बिजली गिरने से 10 की मौत, हाईवे बंद

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में भूस्खलन, छत्तीसगढ़ में पुल टूटने, उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बिहार-झारखंड में आकाशीय बिजली की घटनाओं ने हालात को गंभीर बना दिया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार बारिश से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आकर बंद हो गया है, जिससे चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में भी पहाड़ियों से मलबा गिरने का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रख रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के चलते बिलासपुर-रतनपुर-पेंड्रा मार्ग पर एक पुल बीच से टूट गया। हादसे के समय पुल से गुजर रही एक यात्री बस बीच में फंस गई, हालांकि समय रहते यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मिजार्पुर सहित कई शहरों में तेज बारिश दर्ज की गई। गंगा, घाघरा और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में गंगा का पानी छह गांवों में घुस गया है, जिससे सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। बहसूमा-ठाकुरद्वारा स्टेट हाईवे पर पांच दिनों से पानी बहने के कारण यातायात बंद है। फरुर्खाबाद और वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव और घाट जलमग्न हो गए हैं।

जंगलों की आग बुझाते वक्त दो हेलीकॉप्टर हवा में भिड़े

तूफानी हवाओं और टर्बुलेंस के बीच जारी है राहत कार्य

नेशनल ऑब्जर्वेटरी के वरिष्ठ शोधकताओं ने चेतावनी दी है कि इस तबाही को मेगाफायर की श्रेणी में रखा जाएगा। सिविल प्रोटेक्शन मंत्रालय के अनुसार दमकल विभाग अपनी क्षमताओं की अंतिम सीमा तक जाकर काम कर रहा है। दुखद बात यह है कि इस भयानक आपदा से निपटते हुए और अपना कर्तव्य निभाते हुए पिछले कुछ दिनों में 3 जांबाज दमकलकर्मियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल तूफानी हवाओं और टर्बुलेंस के बीच राहत कार्य जारी हैं।

एथेंस। भीषण जंगलों की आग से सुलगते ग्रीस में राहत और बचाव कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एथेंस के पश्चिमी इलाके पसाथा में रविवार को धधकती आग पर पानी छिड़क रहे दो अग्निशमन हेलीकॉप्टर हवा में आपस में टकरा गए। हवा में रोटर टकराते ही एक हेलीकॉप्टर जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में एक क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश में सर्च एंड रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई हैं।

ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिन देश के लिए बेहद कठिन साबित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य इस समय बेकाबू मौसम की मार झेल रहा है, जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं। इतनी भीषण हवाओं और घने धुएं के कारण दमकल विमानों के लिए पानी भरना और सुरक्षित तरीके से काम कर पाना लगभग असंभव हो गया है।

राजधानी एथेंस से करीब 70 किलोमीटर दूर लोकप्रिय तटीय गांव पोर्टो जेरमेनो के आसपास आग ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। रात भर में पहाड़ों को पार करते हुए आग एथेंस के बाहरी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी, जिसे नियंत्रित करने के लिए करीब 500 दमकलकर्मी मोर्चे पर डटे हुए हैं। पुलिस अधिकारी घर-घर जाकर सायरन बजाते हुए और दरवाजे खटखटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। विशेषज्ञों और मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अकेले पोर्टो जेरमेनो और उसके आसपास 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है।

राफेल-एम और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से बढ़ेगी भारत की समुद्री ताकत

वेब वार्ता, नई दिल्ली। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लेकर चर्चा तेज कर दी है। भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे अत्याधुनिक राफेल-एम लड़ाकू विमानों की तैनाती के करीब आने के साथ ही पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों में चिंता बढ़ गई है। उनका मानना है कि विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर राफेल-एम की तैनाती के बाद भारतीय नौसेना की समुद्री मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।

रक्षा विश्लेषकों के अनुसार, भारत की ताकत केवल राफेल-एम विमानों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसके साथ काम करने वाला पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में बड़ी रणनीतिक बढ़त देगा। इसमें विमानवाहक पोत के अलावा आधुनिक डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियां, सपोर्ट शिप, लंबी दूरी के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बहुस्तरीय एयर डिफेंस नेटवर्क शामिल होते हैं। भारत ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल-एम लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। ये विमान विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालन और समुद्री अभियानों के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें आधुनिक सेंसर, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता और लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार

शामिल हैं। इसकी मेटर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता इसे और प्रभावी बनाती है, जिससे दुश्मन के विमान को दूर से ही निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में चीन से जे-10सीई मल्टीरोल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक, हथियार प्रणाली और समुद्री संचालन क्षमता के मामले में राफेल-एम भारतीय नौसेना को बढ़त दे सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संघर्ष का परिणाम केवल एक विमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सैन्य रणनीति, प्रशिक्षण और संसाधनों के इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है। भारत की नौसैनिक रणनीति केवल विदेशी विमानों तक सीमित नहीं है। स्वदेशी ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर कार्यक्रम पर भी काम जारी है, जिसे भविष्य में नौसेना के मौजूदा लड़ाकू विमानों के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े विमानवाहक पोत की योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान की चिंता का मुख्य कारण यह है कि भारतीय नौसेना अब केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक युद्धपोतों, विमानवाहक पोतों, पनडुब्बियों और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं के साथ भारत हिंद महासागर में ब्लू वॉटर नेवी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। राफेल-एम की तैनाती को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

संपादकीय

गिरती दीवारें: इमारतों का ढहना

इस दरमियानी आधे दशक में, मालिकों ने उक्त संपत्ति को खाली करने या उसे फिर से विकसित करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अनधिकृत मरम्मत का काम किया। जहां जिलानी बिल्डिंग - जो पुरानी तो थी लेकिन खतरनाक इमारतों की सूची में नहीं थी - का गिरना पहले से अंदाजा न लगा पाने की नाकामी थी, वहीं ऐसी सूची में शामिल और मरम्मत के दौरान गिरने वाली कोहिनूर बिल्डिंग का ढहना नियमों को लागू न कर पाने की नाकामी को दर्शाता है। फिर भी, राज्य सरकार ने दोनों ही मामलों में एक जैसा ही रवैया अपनाया - 2020 में अधिकारियों को निलंबित किया था और अब ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। भारत के सबसे बड़े पावरलूम हब में से एक, भिवंडी में कम आय वाले प्रवासी लोगों की बड़ी तादाद घनी आबादी वाले इलाकों में छोटे-छोटे घरों में रहती है। खतरे वाली सूची में सैकड़ों इमारतें होने और कोई ट्रांजिट कैंप या अस्थायी घर न होने के चलते, लोग अक्सर बेघर होने के बजाय असुरक्षित घरों में रहना चुनते हैं। जबकि, मकान मालिक किराया वसूलते रहते हैं। पुलिस की मदद के बिना खाली कराने के आदेशों को लागू करना भी मुश्किल होता है, जबकि इससे नगर निगम को कागजों पर कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर लेने का दावा करने का मौका मिल जाता है। साथ ही, इमारतों को गिराना राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला होता है। मानसून के दौरान दोनों इमारतों का गिरना भी कोई इत्तेफाक नहीं है।

सितंबर 2020 में, महाराष्ट्र के भिवंडी नगर निगम ने ठीक उसी वक्त कोहिनूर बिल्डिंग को अपनी खतरे वाली इमारतों की सूची में डाला था जब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिलानी बिल्डिंग ढह गई थी। उस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। छह साल बाद, अधिकारियों द्वारा कोहिनूर को एक बार फिर से असुरक्षित घोषित करने और लगभग 40 निवासियों को बाहर निकालने के कुछ ही घंटों बाद यह इमारत ढह गई और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई।

भारत में बुनियादी ढांचे को एक बार के निवेश वाली संपत्ति माना जाता है। साल 2000 के दशक के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई, लेकिन उसी रफ्तार से रखरखाव और प्रशासनिक निगरानी नहीं हो पाई। बल्कि प्रशासनिक निगरानी और भी बिखर ही गई। साल 2024 के बीच में दिल्ली, जबलपुर और राजकोट के हवाई अड्डों पर छतें या शेड गिर गए, जबकि 2024-26 के दौरान बिहार में कई पुल ढह गए। श्रेणी-1 वाले शहरों में अक्सर सड़कें धंसने और तहखानों (बेसमेंट) में पानी भरने की घटनाएं हुई हैं। इनमें राजेंद्र नगर की दुखद घटना भी शामिल है। इस साल कोलकाता और पुणे में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। यूं तो ढांचों की लगातार

निगरानी और समय रहते चेतावनी देने वाली तकनीकें मौजूद हैं, फिर भी शहरीकरण की रफ्तार नगर निकायों की क्षमता से कहीं ज्यादा रही है और अधिकांश मामलों में विफलता की वजह पहले से पता खतरे ही रहे हैं। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है - हालांकि मीडिया कवरेज और बुनियादी ढांचों की बढ़ती संख्या भी इसकी एक वजह हो सकती है। लेकिन कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई, जांच, ऑडिट के वादे और पीड़ितों को मुआवजा देने जैसी सरकार की आम प्रतिक्रियाओं के बजाय, भारत की इमारतों को बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार की जरूरत है। इसके लिए शहरी नवीनीकरण (अर्बन रिन्यूअल) ही एकमात्र उपाय है।

क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को नेतृत्व दिया या केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ?

भारतीय राजनीति में कांग्रेस और मुसलमानों के रिश्ते पर दशकों से बहस होती रही है। एक धारणा यह भी है कि कांग्रेस ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सबसे बड़ा वाहक बताया, लेकिन जब बात संगठन और सत्ता में वास्तविक भागीदारी की आई, तो मुसलमानों को अक्सर सीमित और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक ही रखा गया। इस दृष्टिकोण से देखने वाले लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में अधिक महत्व दिया, जबकि निर्णय लेने वाली मुख्य संरचना में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही।

इसी संदर्भ में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से अलग होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना जाता है। लगभग पाँच दशकों तक पार्टी के साथ रहने वाले गुलाम नबी आजाद ने केवल संगठन में ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। इसके बावजूद, जब पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और नई राजनीतिक प्राथमिकताएँ सामने आईं, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो गया है और वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है।

इस विषय पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। पहला यह कि उन्होंने स्वयं असहमति के कारण पार्टी छोड़ी। दूसरा, जो उनके समर्थकों और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह यह है कि उन्हें धीरे-धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया और पार्टी ने नए चेहरों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि यह केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की बदलती राजनीतिक रणनीति का संकेत भी था।

कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो मुस्लिम समुदाय से कई प्रमुख नेता

समय-समय पर उभरे। इनमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अ. फ अंतुले, आरिफ मोहम्मद खान , मोहसिना कि दवई , रशीद मसूद , अहमद पटेल ' और वर्तमान समय में इमरान प्रतगढ़ी जैसे नाम शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि इन नेताओं को प्रमुख चेहरों के रूप में प्रस्तुत अवश्य किया गया, लेकिन पार्टी की सर्वोच्च निर्णय प्रक्रिया और वास्तविक शक्ति संरचना में उनकी भूमिका सीमित रही।

यही कारण है कि समय-समय पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या कांग्रेस ने मुस्लिम नेतृत्व को वास्तव में विकसित किया, या केवल एक-दो बड़े चेहरों के माध्यम से पूरे समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करने का प्रयास किया। यदि किसी समुदाय की आबादी, राजनीतिक भागीदारी और ऐतिहासिक योगदान को देखा जाए, तो यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि उसे संगठन के शीर्ष स्तर पर भी पर्याप्त स्थान मिले।

दूसरी ओर, कांग्रेस का पक्ष यह रहा है कि उसने हमेशा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया और देश के संविधान तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा को प्राथमिकता दी। पार्टी यह भी कहती रही है कि उसके भीतर पद और जिम्मेदारियाँ योग्यता, अनुभव और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर तय होती हैं, न कि केवल धार्मिक पहचान के आधार पर। इसलिए इस विषय को केवल एक समुदाय या कुछ नेताओं तक सीमित करके देखना पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता।

फिर भी, यह प्रश्न अपनी जगह बना रहता है कि स्वतंत्र भारत में इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति की धुरी रहने वाली कांग्रेस मुस्लिम समाज से कितने ऐसे नेताओं को तैयार कर सकी, जो पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व का हिस्सा बने या भविष्य के प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार माने गए। यह प्रश्न केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि लगभग सभी राष्ट्रीय दलों के लिए प्रासंगिक है। लोकतंत्र में किसी भी समुदाय की भागीदारी केवल चुनावी टिकट देने से पूरी नहीं होती। वास्तविक भागीदारी तब मानी जाती है जब नीति निर्माण, संगठन संचालन और निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्थाओं में भी समान अवसर मिले। यदि किसी समुदाय को केवल चुनावी मौसम में याद किया जाए और उसके बाद उसकी राजनीतिक भूमिका सीमित हो जाए, तो असंतोष स्वाभाविक है। आज आवश्यकता किसी एक दल की आलोचना या समर्थन से अधिक इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल प्रतीकात्मक राजनीति से आगे बढ़ें। मुस्लिम समाज सहित देश के प्रत्येक वर्ग को केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति-निमार्ता, संगठन-निमार्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में भी स्थान मिलना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि प्रतिनिधित्व केवल दिखावे का न हो, बल्कि वास्तविक और प्रभावी हो। अंततः यह बहस केवल गुलाम नबी आजाद या किसी एक नेता की नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न की बहस है कि क्या भारत की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदायों को वास्तविक नेतृत्व का अवसर मिल रहा है, या वे अब भी चुनावी गणित का हिस्सा भर बने हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर राजनीतिक दलों को अपने आचरण और संगठनात्मक ढाँचे से देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास केवल नारों से नहीं, बल्कि सहभागिता से मजबूत होता है।

जेन-जी आंदोलन का असर न्यायपालिका पर ?

जंतर मंतर पर हुए जेन-जी आंदोलन का असर पहले जेन-अल्फा पर देखने को मिला है। इसके बाद बाद जिस तरह से न्यायपालिका के बारे में युवा मुखर होकर अपनी बात सोशल मीडिया पर कहने लगे हैं, उससे अंदेशा है कि न्यायपालिका भी निशाने पर आ गई है। कॉकरोच शब्द पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही निकला था। यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा, इसे ना तो सरकार ने सोचा था ना ही न्यायपालिका ने सोचा था, लेकिन जिस तरह से बिना किसी डर और भय के सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अपनी बात कह रहे हैं। इसका असर देश के सभी वर्गों पर पढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां द्वारा न्यायपालिका में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली को लेकर तीखे सवाल किए गए हैं। उसके बाद से यह मामला भी तूल पकड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट अथवा न्यायपालिका में कॉलेजियम द्वारा पहले जजों की नियुक्ति के समय जो अनुशंसा की जाती थीं, उसके कारण भी कॉलेजियम में बताए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कॉलेजियम में जो अनुशंसा की जा रही है उनमें चयन का आधार और उसके कारणों की स्पष्टता नहीं होने से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो निर्णय जजों की नियुक्ति के लिए लिए जा रहे हैं उनकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट में ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ समय से सरकार कॉलेजियम की अनुशंसा को दरकिनार करते हुए मनमाने तरीके से जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। कई जजों की वरिष्ठता को नजर अंदाज करते हुए तथा ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से जजों को सीनियर से जूनियर बनाने और अपने इच्छित व्यक्ति को जज बनाने के लिए कॉलेजियम और सरकार के बीच में जो सांठ-गांठ हो रही है उसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज भी खुलकर बोलने लगे हैं। कॉलेजियम में शामिल जजों द्वारा जो डीसेंट नोट दिया जाता था उसे भी सार्वजनिक नहीं किए जाने पर जस्टिस नागरत्ना द्वारा आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए जजों की नियुक्ति मनमाने तरीके से हो रही है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के बीच में जिस तरह की मुखरता के साथ अपनी बात कही जा रही है न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर अब खुद न्यायपालिका के अंदर से आवाज उठ रही है।

न्यायपालिका का जो डर और भय था लगता है जेन-जी और जेन-अल्फा द्वारा बिना किसी डर और भय के जिस तरह से सड़कों पर आकर अपनी बात कही जा रही है उसने सभी वर्गों का डर और भय निकालने का काम किया है। देशभर में चारों ओर से निष्पक्षता की बात होने लगी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के फैसले और दो तरह के कानून को लेकर जो धारणा बनी है उसको लेकर अब देश भर में न्यायपालिका के प्रति भी आक्रोश देखने को मिलने लगा है। न्यायपालिका के प्रति पहले जो विश्वास राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच में देखने को मिलता था अब वह देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार भी बार-बार कहती है, यदि सरकार का फैसला पसंद नहीं है तो कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से वही फैसला आता है जो सरकार का बचाव करता है। कई राज्य सरकारों को केवल इसलिए गिरा दिया गया कि उनका फैसला समय पर नहीं हुआ। कई मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। जो मौलिक अधिकारों और संविधान से जुड़े हुए थे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी मामला पिछले 2 साल से लंबित पड़ा हुआ है। एसआईआर के मामले में भी चुनाव आयोग को न्यायपालिका का जो सर्वेक्षण मिला है, उसको लेकर तरह-तरह की धारणा न्यायपालिका के प्रति आमजनों के बीच भी बनने लगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहना की लाखों मतदाताओं के नाम यदि मतदाता सूची में नहीं है वह इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल से फैसला होने के बाद अगली बार वोट दे देंगे। अभी तक एसआईआर के माध्यम से लोकसभा चुनाव के समय जो मतदाता सूची थी उसमें से करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार नागरिकों को मिला हुआ था, उससे वह वंचित कर दिए गए। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जिस तरह की गड़बड़ी के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगे, पूर्व की चुनाव व्यवस्था को बदलते हुए मनमाने तरीके से चुनाव आयोग ने नए-नए नियम बनाए, नए-नए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। इस सब की जानकारी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से छुपाई गई। इस सारी गड़बड़ी में कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता चुनाव आयोग को मिलती रही है। लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो

याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं आया। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की गड़बड़ी के आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए थे उनमें से किसी एक का जवाब भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया। चुनाव आयोग की मनमानी को लेकर लगातार राजनीतिक दल आवाज उठाते रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से न्यायपालिका के पूर्व जजों और न्यायपालिका के वर्तमान जजों द्वारा कॉलेजियम और सरकार को आईना दिखाया जा रहा है, तुरंत इस पर पारिदर्शिता के साथ कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही कहा जा सकता है।

लेखक- सनत जैन

विविधताओं का सम्मान और समावेश

हाल ही में चीन में जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानून लागू हुआ है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चीनी राष्ट्र के साझा समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाना है और इसे चीन के विभिन्न जातीय समूहों का व्यापक समर्थन मिला है। लेकिन कुछ बाहरी ताकतें इस कानून को अल्पसंख्यकों को जबरन आत्मसात करने का नाम देकर जनमत को गुमराह कर रही हैं।

चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन के सदस्य के नाते मुझे इस कानून पर हुई चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला था। इसी अनुभव के आधार पर कुछ बातें साझा करना चाहता हूं।

पहला, यह कानून व्यापक सहमति को बढ़ावा देता है और विविधता का सम्मान करता है। चीनी राष्ट्र पांच हजार वर्षों से भी अधिक प्राचीन सभ्यता वाला एक महान राष्ट्र है। लंबे इतिहास में चीन के विभिन्न जातीय समूहों ने एक-दूसरे से सीखते और घुलते-मिलते हुए ऐसी चीनी सभ्यता का निर्माण किया, जिसकी पहचान विविधता में एकता, खुलेपन और समावेश से होती है। विभिन्न जातीय समूहों का रिश्ता ऐसा है कि तुम में मैं, मुझ में तुम की भावना स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। इसलिए अल्पसंख्यकों के जबरन आत्मसात का कथित आरोप महज एक झूठ है।

कानून की दृष्टि से चीन का संविधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सभी जातीय समूह समान हैं तथा किसी भी समूह के विरुद्ध भेदभाव और दमन निषिद्ध है। यह कानून संविधान की इसी भावना का पूर्णत: प्रतिबिंब है। इसके प्रविधान संविधान के सिद्धांतों की पुन: पुष्टि करते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि राज्य समानताओं को बढ़ावा देगा, विविधताओं का सम्मान और समावेश करेगा, विभिन्न जातीय समूहों के बीच पारस्परिक सहयोग व सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करेगा तथा चीनी राष्ट्र की महान एकता की रक्षा करेगा।

व्यावहारिक स्तर पर चीन हमेशा अल्पसंख्यक जातीय समूहों की संस्कृति के संरक्षण को महत्व देता रहता है। शीत्सांग (तिब्बत) के पोताला महल और जोखांग मंदिर जैसे सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। कुतदगु बिलिग सहित विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे अनेक प्राचीन ग्रंथों का चीनी और उइगुर भाषाओं में अनुवाद, संपादन तथा प्रकाशन किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल चीन की 45 परियोजनाओं में से एक-तिहाई से अधिक अल्पसंख्यक जातीय समूहों की संस्कृति से जुड़ी हैं।

दूसरी बात, यह कानून सभी जातीय समूहों के विकास के अधिकार की रक्षा करता है। हाल के वर्षों में चीन के आधुनिकीकरण ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका लाभ अल्पसंख्यक जातीय समूहों को भी व्यापक रूप से मिला है। चीन के अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रों में गरीबी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

शीत्सांग, शिनच्यांग सहित पांच जातीय स्वायत्त क्षेत्रों का सकल क्षेत्रीय उत्पाद 2012 में 515 अरब डालर से बढ़कर 2025 में लगभग 1.21 ट्रिलियन डालर हो गया है। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने कहा है कि चीनी राष्ट्र एक बड़ा परिवार है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को बेहतर जीवन जीना चाहिए। ह्यजातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानूनह्न साझा समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने को अपना प्रमुख विषय बनाता है। इसमें क्षेत्रीय समन्वित विकास को बढ़ावा देने, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों के विकास तथा बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की समानता और सुलभता बढ़ाने के लिए ठोस व विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, ताकि सभी जातीय समूह विकास के लाभ समान रूप से प्राप्त कर सकें। तीसरी बात, यह कानून विभिन्न जातीय समूहों के आपसी मेल-जोल को बढ़ावा देता है। चीन में अल्पसंख्यक जातियों की एक-तिहाई से अधिक जनसंख्या नगरों तथा बिखरे हुए क्षेत्रों में निवास करती है। अल्पसंख्यक जातियों की प्रवासी जनसंख्या 3.3 करोड़ से अधिक हो चुकी है। विभिन्न जातीय समूहों के बीच आपसी मेल-जोल का स्तर एवं इसकी आवश्यकता अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई है। ह्यजातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन कानूनह्न में ऐसे सामाजिक वातावरण के निर्माण पर जोर दिया गया है, जहां विभिन्न जातीय समूह साथ रहें, साथ पढ़ें, मिलकर निर्माण करें, उपलब्धियां साझा करें, साथ काम करें और आनंदपूर्वक जीवन बिताएं। यह कानून चीन की परिस्थितियों के अनुरूप जातीय मुद्दों के सही समाधान का विधिक सार है। यह न केवल चीन के लोगों के हित में है, बल्कि अन्य देशों को भी जातीय मुद्दों से निपटने का उपयोगी अनुभव प्रदान करता है। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं तथा एकीकृत बहुजातीय राष्ट्र हैं। दोनों ने लंबे अनुभव के आधार पर अपनी-अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप जातीय नीतियां विकसित की हैं। चीन भारत के साथ संवाद और आदान-प्रदान को और मजबूत करने का इच्छुक है, ताकि दोनों देश साथ मिलकर राष्ट्रीय शासन के स्तर को उन्नत कर सकें, ग्लोबल साउथ के बहुजातीय देशों के शासन अनुभवों को समृद्ध बना सकें तथा अधिक सौहार्दपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान दे सकें।

(लेखक भारत में चीन के राजदूत)

फिर युद्ध का खतरा

क्या दुनिया एक और महाविनाश की ओर बढ़ रही है ?

पश्चिम एशिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां एक छोटी-सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को भीषण युद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ता तनाव केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शांति, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। यदि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष शुरू होता है तो इसका प्रभाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी।

हाल के दिनों में अमेरिका की ओर से दिए गए कड़े संकेत और ईरान की आक्रामक चेतावनियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि उसके रणनीतिक ठिकानों पर हमला हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया केवल अपने भूभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजरायल को भी इसका सामना करना पड़ सकता है।

युद्ध की भाषा हमेशा विनाश की प्रस्तावना होती है। इतिहास बताता है कि जब राष्ट्र संवाद की बजाय सैन्य शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं तो परिणाम केवल तबाही होता है। अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों से सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है ।परमाणु कार्यक्रम पर अविश्वास ने दोनों देशों के संबंधों को लगातार खराब किया है। आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक, वित्तीय प्रतिबंध और सैन्य दबाव ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। अब यदि यह विवाद खुले युद्ध में बदलता है तो उसके परिणाम केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय भी होंगे।

आधुनिक युद्धों में केवल सैनिकों पर हमला नहीं किया जाता बल्कि विरोधी देश की आर्थिक रीढ़ को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। ऊर्जा प्रतिष्ठान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। तेल रिफाइनरी, गैस संयंत्र, बिजलीघर और पाइपलाइन किसी राष्ट्र की जीवनरेखा हैं। यदि इन पर हमला होता है तो केवल ऊर्जा उत्पादन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार व्यवस्था और आम नागरिकों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है ।ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है। ऐसे में उसके ऊर्जा ढांचे पर किसी भी प्रकार का हमला वैश्विक तेल बाजार को तुरंत प्रभावित कर सकता है।

दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे संवेदनशील बिंदु होर्मुज जलडमरूमध्य माना जाता है। विश्व के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है ।यदि युद्ध की स्थिति में यह मार्ग बाधित होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं ।पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, विमान ईंधन और बिजली उत्पादन की लागत बढ़ने से महंगाई तेज होगी। परिवहन से लेकर खाद्य पदार्थों तक हर क्षेत्र प्रभावित होगा। भारत के पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में कार्यरत हैं और भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है।

भारत पहले भी पश्चिम एशिया के संकटों के दौरान अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े अभियान चला चुका है। इसलिए किसी भी नए संघर्ष की स्थिति में भारत को कूटनीतिक और मानवीय दोनों स्तरों पर तैयार रहना होगा। ईरान ने संकेत दिए हैं कि यदि उस पर हमला होता है तो वह केवल अपने क्षेत्र की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के अनेक सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, जॉर्डन और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति लंबे समय से बनी हुई है। यदि इन ठिकानों पर हमले होते हैं तो संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई देश अनचाहे रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। यही किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष को वैश्विक संकट में बदलने का सबसे बड़ा कारण बनता है।

इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से गहरा तनाव रहा है। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष और परोक्ष टकराव समय-समय पर सामने आते रहे हैं। यदि अमेरिका किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है तो इजरायल की सुरक्षा स्वत: एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी। दूसरी ओर ईरान पहले भी संकेत देता रहा है कि वह इजरायल को अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। ऐसी स्थिति में पूरा पश्चिम एशिया कई मोर्चों वाले युद्ध का मैदान बन सकता है ।तनाव के बीच यह चर्चा भी तेज है कि रूस ईरान को विभिन्न प्रकार की तकनीकी या खुफिया सहायता उपलब्ध करा सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भी सीमित रही हैं। फिर भी यदि बड़ी शक्तियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी संघर्ष में शामिल होती हैं तो क्षेत्रीय युद्ध का दायरा और व्यापक हो सकता है।

आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का प्रभाव वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। युद्ध कभी अचानक नहीं होता। उसके पहले वर्षों तक अविश्वास, आरोप-प्रत्यारोप, आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य तैयारियां और असफल वार्ताएं चलती रहती हैं ।दुर्भाग्य यह है कि आज वैश्विक कूटनीति पहले की तुलना में अधिक कमजोर दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं लगातार अपील तो करती हैं, लेकिन महाशक्तियों के सामने उनकी प्रभावशीलता सीमित नजर आती है। यदि संवाद की प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी तो सैन्य विकल्प हमेशा अधिक आकर्षक प्रतीत होने लगेंगे। युद्ध का निर्णय नेता लेते हैं लेकिन उसकी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं ।बम सैनिक अड्डों पर ही नहीं गिरते, वे अस्पतालों, स्कूलों, घरों और बाजारों को भी प्रभावित करते हैं। लाखों लोग विस्थापित होते हैं, बच्चों की शिक्षा रुक जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं और वर्षों तक समाज अस्थिर रहता है ।इराक, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान इसके बड़े उदाहरण हैं, जहां युद्ध समाप्त होने के बाद भी सामान्य जीवन लौटने में वर्षों लग गए।

इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि सैन्य जीत हमेशा राजनीतिक समाधान नहीं बनती। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया के उदाहरण बताते हैं कि युद्ध शुरू करना अपेक्षाकृत आसान होता है लेकिन शांति स्थापित करना बेहद कठिन ।यदि उद्देश्य केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रह जाए और राजनीतिक समाधान पीछे छूट जाए तो संघर्ष वर्षों तक चलता रहता है ।भारत परंपरागत रूप से रणनीतिक स्वायत्तता और संतुलित विदेश नीति का समर्थक रहा है ।भारत के अमेरिका से भी मजबूत संबंध हैं और ईरान के साथ भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा ऊर्जा संबंध महत्वपूर्ण रहे हैं।

ऐसी स्थिति में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शांति, संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के पक्ष में प्रभावी भूमिका निभाए ।संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि विश्व युद्ध जैसी त्रासदियां दोबारा न हों। आज आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, यूरोपीय संघ, अरब लीग और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंच सक्रिय होकर दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की दिशा में ठोस पहल करें। यदि कूटनीति विफल होती रही तो दुनिया बार-बार युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई देगी।

अमेरिका और ईरान दोनों शक्तिशाली राष्ट्र हैं। दोनों के पास सैन्य क्षमता है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। विश्व नेतृत्व का अर्थ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि संयम भी होता है ।यदि दोनों देश वार्ता की मेज पर लौटते हैं तो न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी ।पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव केवल दो देशों का विवाद नहीं है; यह पूरी मानवता की चिंता का विषय है। ऊर्जा संकट, वैश्विक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और करोड़ों लोगों का भविष्य इस संघर्ष से प्रभावित हो सकता है। किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले यह याद रखना होगा कि युद्ध का अंत चाहे जिस रूप में हो, उसकी शुरूआत हमेशा मानवता की हार से होती है। दुनिया पहले ही अनेक संकटों से जूझ रही है। ऐसे समय में एक और व्यापक युद्ध किसी के हित में नहीं होगा। आज आवश्यकता शक्ति प्रदर्शन की नहीं, बल्कि धैर्य, संवाद, विश्वास और कूटनीतिक समाधान की है। यदि विश्व समुदाय समय रहते सक्रिय नहीं हुआ तो पश्चिम एशिया की यह आग सीमाओं को पार कर वैश्विक संकट का रूप ले सकती है। इतिहास गवाह है कि युद्ध जीतने वाले भी अंतत: शांति की तलाश में ही लौटते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि शांति का रास्ता युद्ध शुरू होने से पहले ही खोज लिया जाए।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर अर्पण केंद्र का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर अर्पण केंद्र का शुभारंभ किया। यह पहल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) एवं दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पुराने उपयोग योग्य वस्त्रों का संग्रह, रीयूज, रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से वस्त्र दान प्रक्रिया का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सड़कों, पुलों और मेट्रो लाइनों से नहीं होता, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों, संसाधनों के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक भावना से होता है। जब अपशिष्ट को संसाधन में बदला जाता है और विकास के साथ प्रकृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, तभी वास्तविक अर्थों में विकसित समाज का निर्माण होता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पुराने वस्त्रों का रीसाइक्लिंग केवल कचरा कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी प्रभावी उपाय है। प्रत्येक नागरिक द्वारा दान किया गया एक वस्त्र पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसी जरूरतमंद के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने बताया कि इस परिकल्पना के तहत दिल्ली मेट्रो के 10 प्रमुख स्टेशनों पर ये केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जिसमें पहले चरण के तहत आज 5 प्रमुख स्टेशनों, शालीमार बाग, पंजाबी बाग वेस्ट, मयूर विहार फेस-1, शाहदरा और रोहिणी वेस्ट पर अर्पण केंद्रों की शुरूआत कर दी गई है। इसके लिए संबंधित संस्थाओं के बीच औपचारिक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हो चुका है। सभी चयनित मेट्रो स्टेशनों पर टेक्सटाइल कलेक्शन-कम-सेल कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं, जहां नागरिक अपने उपयोग योग्य पुराने वस्त्र दान कर सकेंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए वस्त्र दान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाया गया है। दानकर्ता क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के माध्यम से आसानी से अपने पुराने कपड़े दान कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल रिसिप्ट भी प्राप्त होगी। इससे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसा ह्यदिल्ली मॉडलह्ल विकसित करना है, जहां कचरा नहीं बल्कि संसाधन दिखाई दें, उपभोग नहीं बल्कि उत्तरदायित्व दिखाई दे और विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण राजधानी की पहचान बने। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन और सभी सहयोगी संस्थाओं को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान जनभागीदारी के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ, हरित, संवेदनशील एवं टिकाऊ शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मादीपुर से विधायक कैलाश गंगवाल, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार, दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की अध्यक्ष डॉ. शालिनी सिंह, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे।

सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपर्ण भूमिका निभाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। इन केंद्रों के संचालन, वस्त्रों के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उनके लिए सम्मानजनक आजीविका एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण का यह समन्वित मॉडल दिल्ली के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार सदैव ऐसे इनोवेशन को प्रोत्साहित करती रहेगी जो पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन तथा जनभागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाते हों। यह पहल देश में सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने और ह्यवेस्ट टू वेल्थह्ल की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में रखे उपयोग योग्य पुराने कपड़ों को अर्पण केंद्रों तक अवश्य पहुंचाएं। नागरिकों का एक छोटा-सा योगदान न केवल लैंडफिल में जाने वाले टेक्सटाइल कचरे को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के संरक्षण और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संक्षिप्त वार्ता

केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन पर सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया और देश के लिए मेडल जीते। सभी खिलाड़ियों पर देशवासियों को बहुत गर्व है। केजरीवाल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी की क्षमता को देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में भारत मेडल तालिका में सबसे ऊपर होगा। जमीनी स्तर पर सोच-समझकर किए गए निवेश और खिलाड़ियों को सही ढांचागत सहयोग अद्भुत परिणाम दे सकते हैं।

डीयू में मिड एंट्री से दाखिले के लिए शुरू हुआ पंजीकरण

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)। डीयू ने स्नातक पाठ्यक्रमों में मिड एंट्री के माध्यम से दाखिले के लिए सोमवार से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने अब तक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-यूजी 2026) के तहत आवेदन नहीं किया था या किसी कारणवश पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे। यह प्रक्रिया पांच जुलाई तक चलेगी। विश्वविद्यालय के अनुसार, मिड एंट्री विंडो के माध्यम से नए अभ्यर्थी सीएसएएस पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी पसंद के कॉलेजों और पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। इस दौरान निर्धारित मिड एंट्री शुल्क भी जमा करना होगा। यह सुविधा आगामी आवंटन चरणों में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि डीयू इस वर्ष भी स्नातक प्रवेश के लिए सीयूईटी (यूजी) के अंकों के आधार पर सीएसएएस के माध्यम से दाखिले कर रहा है। पहले और दूसरे आवंटन चरण के बाद जिन सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाया है, उन्हें भरने के लिए मिड एंट्री की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिल सके।

एनडीटीएफ ने शुरू की जनहित याचिका

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) ने उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा और शिक्षाविदों पर राजनीतिक हमलों के विरोध में लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित एक जन याचिका शुरू की है। संगठन के अनुसार, अब तक 600 से अधिक शिक्षकों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। याचिका में आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी समेत शिक्षाविदों के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लेने और सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। साथ ही विश्वविद्यालयों को राजनीतिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक अपमान और प्रतिशोध से सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। संगठन का कहना है कि देश की प्रगति के लिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षाविदों का सम्मान आवश्यक है।

आईजीआई पर पकड़ा गया 2.76 किलो गांजा

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)। आईजीआई एयरपोर्ट के सीमा शुल्क (कस्टम्स) अधिकारियों ने एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर कार्रवाई करते हुए फुकेत से दिल्ली पहुंचे एक यात्री के पास से करीब 2.76 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया है। कस्टम्स के अनुसार, यात्री 2 अगस्त को एयर इंडिया की उड़ान एआई-2377 से फुकेत से दिल्ली पहुंचा था। ग्रीन चैनल पर उसे रोककर उसके सामान की एक्स-रे जांच की गई, जिसमें संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद विस्तृत तलाशी में बैग से हरे रंग के पदार्थ के चार पैकेट बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में यह हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) प्रतीत हुआ, जिसका कुल वजन पैकेजिंग सहित 2,759.5 ग्राम है। कस्टम्स ने मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

केजरीवाल मंगलवार को इथेनॉल नीति के विरोध में प्रधानमंत्री के आवास तक निकालेंगे मार्च

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की इथेनॉल नीति का विरोध करते हुए मंगलवार (कल) को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथेनॉल के खिलाफ 2.33 लाख से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपने का प्रयास करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिना पर्याप्त तर्क दिए देश पर इथेनॉल नीति थोप रही है, जिससे लोगों की गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है और वाहन प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के पीछे कोई एजेंडा है।

केजरीवाल ने दावा किया कि हाल ही में कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित इथेनॉल मुद्दे पर पार्टी का टाउन हॉल कार्यक्रम सफल रहा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को लगभग सात लाख लोगों ने लाइव देखा। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल नीति का विरोध करने वाले लोगों, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को डराया-धमकाया जा रहा है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन चलाई गई याचिका पर दो लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने लगभग एक महीने पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पत्र लिखकर समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए अब वे मंगलवार को दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे और याचिका व्यक्तिगत रूप से सौंपने का प्रयास करेंगे।

नजफगढ़ ड्रेन पर बनेगा नया एफओबी, पुरानों का होगा ऑडिट

नई दिल्ली, वेब वार्ता

नजफगढ़ ड्रेन पर नया फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने के कार्य का सोमवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों की वर्षों से यहां एफओबी बनाने की मांग थी। लगभग सात माह में पूरा होने वाला यह पुल हजारों लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। मंत्री ने दिल्ली के विभिन्न पुलों एवं फ्लाईओवरों के व्यापक ऑडिट कराने की बात भी इस दौरान कही।

शुभारंभ के अवसर पर मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली सरकार की नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह नया फुटब्रिज गुड़ मंडी, राजपुरा, रूप नगर, मुखर्जी नगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। इसके बनने से विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, कार्यालय जाने वाले लोगों तथा स्थानीय निवासियों को लंबे समय से चली आ रही आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

उन्होंने कुछ महीने पहले हुई पुल दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि राजधानी में पुलों की नियमित संरचनात्मक जांच बेहद आवश्यक है।

पिछली सरकार के दौरान पुलों का कोई व्यापक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की समय पर जांच नहीं हो सकी। आज दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुलों, फ्लाईओवरों और फुटओवर ब्रिजों का व्यापक ऑडिट करा रही है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में घर की छत गिरने से दंपति की मौत, बच्चा बचा

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के अनुसार, जय प्रकाश नगर के एच ब्लॉक में एक घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे की छत गिर गई। इस हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। हादसे के समय उनका छोटा बच्चा कमरे में मौजूद था, जो सुरक्षित बच गया।

अधिकारियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, छत रात करीब 9:30 बजे गिरी। हालांकि, दिल्ली फायर सर्विसेज को घटना की जानकारी रात करीब 11:30 बजे मिली, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। दंपति को मलबे से बाहर निकाला गया और पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बच्चे की जान बच गई। लोगों ने आरोप लगाया कि इमारत बहुत खराब हालत में थी और कुछ समय से उसमें स्ट्रक्चरल कमजोरी के लक्षण दिख रहे थे। एक पड़ोसी, सोनू ने कहा, ह्यइस घर की हालत बहुत खराब थी। इमारत खतरनाक हालत में थी। गली में आगे जाकर देखा जा सकता है कि कुछ और घरों की छतें भी गिर गई हैं। मैंने उन्हें पहले ही कमरा खाली करने की सलाह दी थी। मुझे आज सुबह इस घटना के बारे में पता चला। मैं उनका पड़ोसी हूं।

पुलिस और सिविक अधिकारियों ने इमारत गिरने का सही कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद एक बार फिर दिल्ली के कई हिस्सों में पुरानी और खराब मेंटेनेंस वाली इमारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में इमारत गिरने के एक हादसे के बाद यह घटना घटी है। बीते महीने जुलाई में, रोहिणी सेक्टर 16 में भारी बारिश के बाद एक अंडर-कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। दिल्ली फायर सर्विस के 4 दमकल वाहन, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें बचाव अभियान के लिए मौके पर तैनात की गईं। स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुट गए। मलबे के नीचे से आवाजें सुनकर उन्होंने अपने हाथों से ही ईंटें, कंक्रीट के स्लैब और मुड़ी हुई लोहे की राड्स हटाना शुरू कर दिया।

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर की ओर किया मार्च, कई कार्यकर्ता हिरासत में

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के हजारों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में ह्यछात्र न्याय मार्चह्ल निकाला। यह मार्च जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कथित हिंसा, पैलेट गन के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया।

मार्च एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू होकर जंतर-मंतर की ओर बढ़ा। इस दौरान छात्रों और कार्यकर्ताओं ने न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर नारे लगाए। मार्च को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और रास्ते में बैरिकेडिंग की गई। इस दौरान एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों के साथ हुए व्यवहार के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्र इस देश का भविष्य हैं, अपराधी नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल, पैलेट गन, बैरिकेडिंग और हिरासत का इस्तेमाल पूरी तरह अस्वीकार्य है। छात्रों की आवाज दबाने की हर कोशिश हमारे संघर्ष को और मजबूत करेगी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की भी कड़ी निंदा की।

दबा नहीं सकती है युवाओ की आवाज

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं को डराने और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास है। जाखड़ ने कथित चंदा चोरी के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके खिलाफ जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार से देश के छात्रों और युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकती है।

इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थेरेपी से दूर होगा घुटनों और गर्दन का दर्द

नई दिल्ली, 03 अगस्त (वेब वार्ता)। स्ट्रोक, कमर व गर्दन दर्द, घुटने की चोट से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में हाई इंटेंसिटी फोकस्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी सुविधा की शुरूआत हो गई है। इसके लिए अस्पताल में खास मशीन को स्थापित किया गया है। इस थेरेपी की मदद से बिना किसी ऑपरेशन या दर्दनाक प्रक्रिया के मांसपेशियों और नसों को फिर से सक्रिय किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे बुजुर्ग जिनकी चाल में असंतुलन देखने को मिलता है उसको भी थेरेपी की मदद से दूर किया जा सकेगा।

अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग की प्रमुख डॉ. पूजा सेठी ने बताया कि यह थेरेपी बिना किसी ऑपरेशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा की मदद से शरीर की गहरी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इससे मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। शरीर का संतुलन बेहतर होता है। मरीज जल्दी सामान्य गतिविधियां करने में सक्षम हो सकते हैं। यह तकनीक कुछ ही मिनटों में हजारों बार मांसपेशियों को ऐसे सिकोड़ती है जो सामान्य व्यायाम से मुमकिन नहीं है।

इस सुविधा का लाभ स्ट्रोक से उबर रहे मरीजों, लंबे समय से कमर दर्द से पीड़ित, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे मरीजों, खेल संबंधी चोटों, घुटने की समस्याओं, उम्र के साथ होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी और पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा। साथ ही मरीजों को पारंपरिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की असुविधा के बिना बेहतर उपचार मिल सकेगा। थेरेपी की सुविधा मरीजों को सोमवार से शनिवार सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक मिलेगी। हालांकि इसके लिए पहले मरीज का मूल्यांकन किया जाएगा। मरीजों के लिए यह सुविधा पूरी तरह से निशुल्क है।

मरीजों की कार्यात्मक क्षमता में होगा सुधार

थेरेपी सुविधा के उद्घाटन के मौके पर अस्पताल की निदेशक डॉ. अखिलदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि इस थेरेपी सिस्टम की स्थापना संस्थान की साक्ष्य आधारित एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह तकनीक मरीजों के लिए उपलब्ध समग्र उपचार सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगी। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विवेक दीवान और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. हिमांशु महापात्रा ने कहा कि नवीन तकनीकों का समावेश फिजियोथेरेपी सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे मरीजों की कार्यात्मक क्षमता में सुधार और उपचार परिणाम बेहतर होंगे।

प्रॉपर्टी विवाद में पत्नी की हत्या: हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर रची साजिश, मथुरा से आरोपी गिरफ्तार

वेब वार्ता, अब्दुल रशीद

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिला पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के सनसनीखेज मामले का पदार्फाश करते हुए मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के लिए एक हॉलीवुड फिल्म से प्रेरणा ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की मदद से आरोपी को उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने धीरे-धीरे हिंसक रूप ले लिया और आरोपी ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने हत्या की योजना बनाने और पुलिस से बचने के तरीके एक हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर तैयार किए थे,

ताकि वारदात को दुर्घटना या सामान्य घटना का रूप दिया जा सके।

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके चलते पूर्वी जिला पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (उऊफ़) और अन्य तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। कई राज्यों में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई और अंततः तकनीकी ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने आरोपी को मथुरा रेलवे स्टेशन के निकट से दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12,75,000 नकद तथा वारदात और फरारी के दौरान इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी बरामद की। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद नकदी का संबंध संपत्ति विवाद से है या किसी अन्य आर्थिक लेन-देन से।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि हत्या की साजिश में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं तथा घटना की योजना कितने समय पहले बनाई गई थी। पुलिस डिजिटल उपकरणों, बैंक लेन-देन और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से सुलझाने में सफलता हासिल की है। अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और तकनीकी निगरानी ने आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही अदालत में आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

संक्षिप्त वार्ता

सेवानिवृत्त सफाई कर्मी को 72 घंटे के भीतर मिला 7,48,800 का अवकाश नगरीकरण भुगतान

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। आदर्श नगर पालिका परिषद,बलरामपुर में अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू' एवं अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य के नेतृत्व में कर्मचारियों के हित में एक सराहनीय पहल की गई है। पहली बार किसी सेवानिवृत सफाई कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के मात्र 72 घंटे के भीतर अर्जित अवकाश नगरीकरण की संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी श्रीमती हजारा ने अपनी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद आवश्यक अभिलेखीय एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण कर उनके अर्जित अवकाश नगरीकरण की 7,48,800 (सात लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) की धनराशि का भुगतान 3 अगस्त 2026 को कर दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ.धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू' ने कहा कि नगर पालिका के प्रत्येक कर्मचारी का सम्मान एवं उनके वैधानिक देयों का समयबद्ध भुगतान परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कर्मचारियों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अनावश्यक भागदौड़ से मुक्ति दिलाना परिषद की कार्यसंस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पांच साल पुराने चकबंदी वाद जल्द निपटाएं: डीएम

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने चकबंदी कार्यों में तेजी लाने और वर्षों से लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और चकबंदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप संचालित हो।

सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम ने जनपद में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित किए जाएं। चकबंदी अभिलेखों का नियमित सत्यापन किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए।

डीएम ने विशेष रूप से पांच वर्ष से लंबित चकबंदी वादों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में पूरी सावधानी बरती जाए और सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाए। साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए चकबंदी प्रक्रिया को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, एसओसी, सीओ चकबंदी शकील अहमद सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोशल मीडिया टीम की अहम बैठक

आगामी चुनावों की डिजिटल रणनीति पर हुआ मंथन

लखनऊ, वेब वार्ता

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय में सोमवार को कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन की डिजिटल रणनीति, सोशल मीडिया नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने तथा कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए व्यापक चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं और सोशल मीडिया टीम के पदाधिकारियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीतिक संवाद और जनसंपर्क का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में संगठन की ऑनलाइन उपस्थिति को और अधिक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पार्टी के संदेश को तेजी से पहुँचाने की आवश्यकता है।

चर्चा में आगामी चुनावों के मद्देनजर बूथ स्तर तक डिजिटल नेटवर्क विकसित करने, जिला एवं ब्लॉक स्तर की सोशल मीडिया टीमों को सक्रिय करने, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समन्वित अभियान चलाने तथा पार्टी की गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जुड़े जनहित के मुद्दों को तथ्यात्मक एवं प्रभावशाली तरीके से जनता के सामने रखा जाएगा। साथ ही कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रमों, जन आंदोलनों, जनसंपर्क अभियानों और वरिष्ठ नेताओं की गतिविधियों को अधिक व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाएगा ताकि आम नागरिकों तक पार्टी की आवाज प्रभावी ढंग से पहुँच सके।

पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया टीम से आह्वान किया कि वे सकारात्मक, तथ्याधारित और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस की विचारधारा, संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र तथा जनता के अधिकारों से जुड़े संदेशों को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें। इसके लिए आधुनिक डिजिटल उपकरणों, रचनात्मक सामग्री (कंटेंट), वीडियो, ग्राफिक्स और लाइव संवाद जैसे माध्यमों का अधिक उपयोग करने पर भी बल दिया गया। बैठक में संगठन की डिजिटल मजबूती को आगामी चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और पार्टी की नीतियों, योजनाओं तथा जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और नए स्वयंसेवकों को सोशल मीडिया अभियान से जोड़ने की कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के अंत में उपस्थित पदाधिकारियों और सोशल मीडिया टीम के सदस्यों ने आगामी चुनावों में कांग्रेस के डिजिटल अभियान को अधिक संगठित, सक्रिय और प्रभावशाली बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर-14 बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। स्पोर्ट्स स्टेडियम, हरदोई में सोमवार को अंडर-14 बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्र ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर सह संयोजक एवं खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रभास कुंवर श्रीवास्तव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रतियोगिता की रूपरेखा एवं विभिन्न खेलों की जानकारी दी।

उद्घाटन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा टॉस कराकर कुश्ती एवं बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कराया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। बैडमिंटन बालिका वर्ग में कछौना ने प्रथम तथा टोडरपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में टोडरपुर की टीम विजेता रही। हैंडबॉल बालिका वर्ग में पिहानी ने प्रथम एवं भरखनी ने द्वितीय स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में भी पिहानी ने पहला तथा भरखनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। टेबल टेनिस बालिका वर्ग में सण्डीला प्रथम और कछौना द्वितीय स्थान पर रहा। वहीं बालक वर्ग में कछौना ने प्रथम तथा सण्डीला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संचालन जिला व्यायाम शिक्षिका शिमला सिंह एवं जिला व्यायाम शिक्षक के.बी. अवस्थी ने किया।

10 दिन चलेगा अंगदान अभियान: एक अंगदान से आठ लोगों को मिलती है जिन्दगी

वेब वार्ता, कानपुर। युग दधीचि संस्थान 3 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक विशेष राष्ट्रीय अंगदान दिवस जागरुकता मुहिम चलाने जा रहा है। सोमवार को बाल भवन, फूल बाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में अभियान प्रमुख मनोज सेंगर ने बताया कि जो लोग अपने अंगदान का संकल्प लेना चाहें वे फोन नम्बर 9839161790 अथवा 9453482790 पर फोन या फिर वाट्सएप कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दस दिन में जिनका भी पंजीकरण हो जायेगा उन सबको 13 अगस्त अन्तरराष्ट्रीय अंगदान दिवस पर समारोह पूर्वक प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।

युग दधीचि अभियान के प्रमुख मनोज सेंगर ने बताया अंगदान कब और कैसे किया जा सकता है,इसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब ब्रेन डेथ हो जाये और क्लीनिकल डेथ कुछ समय में होने वाली हो उस समय में शासकीय कमेटी की देख रेख में परिजनों की लिखित सहमति से अंगदान लिया जा सकता है। समस्त प्रक्रिया शासन की कड़ी निगरानी में सम्पन्न की जाती है। इसके लिये भारत सरकार की संस्था (एनओटीटीओ) नेशनल ऑर्गन एण्ड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन अपनी

राज्य स्तरीय कमेटी को निर्देशित करती है और यह कमेटी स्थानीय शासकीय टीम की मदद से अंगदान प्राप्त करती है। अंगदान में नेत्रदान संकल्प भी शामिल है। वार्ता में देहदान अभियान प्रमुख मनोज सेंगर के साथ विहिप के प्रान्तीय अध्यक्ष राजीव माहना, रेडक्रास चेयरपर्सन डा० उमेश पालीवाल, उत्कर्ष अकादमी निदेशक डा० प्रदीप दीक्षित एवं एक्स सर्विसमैन लीग अध्यक्ष मेजर योगेन्द्र कटियार शामिल रहे।

एक स्वस्थ व्यक्ति के अंगदान से दो आँखें, दो किडनी, हृदय, यकृत अग्नाशय और फेफड़े आठ लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। इन अंगों का जीवनकाल बहुत कम होने के कारण इन्हें तत्काल निर्धारित समय में अस्पताल तक ले जाने की प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है, केवल हमारी आँख ही सात घण्टे तक जीवित रह पाती है इस कारण नेत्रदान आसान है।

मनोज सेंगर ने बताया कि गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हैपेटाइटिस बी, सेप्टीसीमिया, कोविड, एच आई वी से पीड़ित व्यक्तियों का अंगदान अथवा देहदान नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इन दस दिनों में विद्यालयों, संस्थाओं और संगठनों के बीच जाकर समाज में अंगदान के प्रति फैली भ्रान्तियों को दूर कर अंगदान की उपयोगिता पर बात होगी।

श्रावण के पहले सोमवार पर मातम

गंगाजल लेने गए दो किशोर गंगा में समाए, तीसरे की बची जान

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई।श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर कांवड़ यात्रा के लिए गंगाजल लेने पहुंचे तीन युवकों के साथ कुसुमखोर गंगा घाट पर दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा की मुख्य धारा में स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से दो किशोर लापता हो गए, जबकि तीसरे युवक को स्थानीय गोताखोरों ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की खबर मिलते ही घाट पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों किशोरों की तलाश में युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया।

पुलिस के अनुसार थाना अरवल क्षेत्र के ग्राम चौसार निवासी नारद पुत्र गोविंदराम (15), ऋषि पुत्र छदामी (15) और शिवम पुत्र सुनील (21) सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे कुसुमखोर गंगा घाट पर गंगाजल लेने पहुंचे थे। घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें केवल चिन्हित सुरक्षित घाट पर स्नान करने की सलाह दी थी, लेकिन तीनों युवक आगे बढ़कर गंगा की मुख्य धारा में उतर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही देर बाद तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण नारद और ऋषि का संतुलन बिगड़ गया और दोनों देखते ही देखते गंगा की लहरों में समा गए। घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो स्थानीय गोताखोर बिना देर किए नदी में कूद पड़े। काफी मशक्कत के बाद शिवम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन नारद और ऋषि का कोई पता नहीं चल सका।

घटना की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी सवायजपुर अंकित तिवारी, नायब तहसीलदार राजेश पटेल, थानाध्यक्ष अरवल अनिल कुमार सिंह, अग्निशमन अधिकारी गौतम चौहान, पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों के साथ कई घंटे तक तलाश अभियान चलाया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक दोनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका था।

श्रावण के पहले सोमवार को हुए इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु जमा हो गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और हर किसी की निगाहें रेस्क्यू अभियान पर टिकी हैं। प्रशासन का कहना है कि दोनों किशोरों की तलाश लगातार जारी है।

पुलिस का पक्ष

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि तीनों युवक पुलिस और स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद चिन्हित सुरक्षित घाट छोड़कर गंगा की मुख्य धारा में चले गए थे। इसी दौरान दो किशोर तेज बहाव में डूब गए, जबकि शिवम को स्थानीय गोताखोरों ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश लगातार जारी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से गंगा में केवल चिन्हित एवं सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की।

गन्ने के नई प्रजाति के साथ, मानसून गन्ना बुआई अभियान का मनकापुर मिल्स द्वारा किया गया शुभारंभ

वेब वार्ता, कमर खान

रेहरा बाजार / बलरामपुर। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड अंतर्गत मनकापुर यूनिट के जोन गेट -3 अंतर्गत मानसून गन्ना बुआई अभियान का शुभारंभ एजीएम (केन) नरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक महाप्रबंधक (गन्ना) नरेंद्र सिंह के कर कमलो द्वारा ग्राम सभा बैरिया सुर्जनपुर में कृषक निरंकार सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए गन्ने के बीज से किया गया। इस अवसर पर एजीएम (केन) द्वारा किसानो को जानकारी देते हुए विभिन्न वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीकों को अपनाकर गन्ना कृषि से उचित लाभ पाने का उचित सलाह भी दिया गया और यह भी बताया कि के उचित विधि से गन्ने की बुवाई व बेहतर किसी प्रबंधन अपनाने से गन्ने की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी। इस दौरान उन्होंने किसानों से यह अपील भी किया है कि गन्ने की बुवाई समय पर करें।

इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड मनकापुर इकाई के प्रवीण कुमार तोमर विकास वीर सिंह व भारी संख्या में किसान दशरथ सिंह, राजेंद्र वर्मा, बच्छराज वर्मा, राजकुमार सिंह, राजकुमार वर्मा, अभिमन्यु सिंह, अर्जुन वर्मा आदि उपस्थित रहे।

हरदोई में गुरु पूजा महोत्सव धूमधाम से संपन्न

1100 से अधिक प्रेमियों ने लिया हिस्सा

सपोर्ट सेंटर हरदोई के तत्वावधान में लखनऊ रोड स्थित एक लॉन में गुरु पूजा महोत्सव श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में 1100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी त्रिवेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

वेब वार्ता, हरदोई

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों के लिए भोजन, हलवा, चाय और पोहा की व्यवस्था की गई। वहीं मुख्य द्वार पर राहगीरों एवं कांवड़ यात्रियों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विश्व शांति शिक्षा कार्यक्रम के संस्थापक परम आदरणीय डॉ. श्री प्रेम रावत के ऑनलाइन प्रवचनों का सामूहिक श्रवण किया गया।

स्वयंसेवकों का व्यक्त किया गया आभार

गुरु पूजा के लिए तैयार की गई आकर्षक स्टेज की सभी ने मुक्तकंठ से सराहना की। स्टेज की सजावट एवं व्यवस्था के लिए अंजली यादव और अन्नू गुप्ता की टीम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लगभग 80 स्वयंसेवकों ने तन, मन और धन से सहयोग दिया। ऑडियो-वीडियो व्यवस्था में विवेक गुप्ता की सेवाओं की विशेष सराहना की गई। साथ ही ओमप्रकाश कश्यप, सुधीर यादव, गिरजेश सिंह, संगीता कश्यप, नीलम मिश्रा, यूट्यूबर बहन जी सहित सभी स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया गया।

प्रेम रावत के संदेशों को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु आध्यात्मिक वातावरण में भावविभोर नजर आए।

गुरु पूजा के महत्व पर रामरतन शर्मा, बृज किशोर दीक्षित, सुशील कुमार श्रीवास्तव, कुसुम कुमारी, दीप कुमार सोनी, शिव स्वरूप राठौर एवं मनोज कुमार गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं पीके गुप्ता ने न्यू वेंचर के विभिन्न स्तंभों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में तथा हड्डक्रू से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने सभी अनुयायियों से का सब्सक्रिप्शन लेने तथा #अनमोल खजाना# से जुड़ने की अपील भी की।

समारोह में लंबे समय से जुड़े प्रेमियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले बच्चों को मुख्य अतिथि जेपी त्रिवेदी ने मेडल एवं उपहार देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के समापन पर भजनों की मधुर प्रस्तुतियों पर प्रेमी झूम उठे। लाइव प्रसारित भजनों पर उपस्थित श्रद्धालु आनंद और भक्ति में सराबोर होकर नृत्य करते रहे तथा जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। अंत में कार्यक्रम के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन अस्मिता ने किया।

उद्यान विभाग की योजनाओं को मिली मंजूरी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। कलेक्ट्रेट स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उद्यान विभाग की विभिन्न औद्यानिक विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए सभी योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए औद्यानिक विकास योजना, आम फलपट्टी, हर्बल गार्डेन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रो इरिगेशन), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा पोस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम की समीक्षा की गई। जिला उद्यान अधिकारी ने योजनाओं की प्रगति और प्रस्तावों की जानकारी प्रस्तुत की। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में मौजूद प्रगतिशील किसानों से संवाद कर उनके अनुभव जाने। इस दौरान संडीला क्षेत्र की किसान सोनाली सब्बरवाल ने अपनी मशरूम उत्पादन इकाई में तैयार मशरूम और भरावन के ओमप्रकाश मौर्य ने अपने उत्पादित शहद का प्रदर्शन किया। इसके अलावा केला, आम, ड्रैगन फ्रूट, मशरूम और सब्जी उत्पादन से जुड़े कई प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

सकाहा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद डीएम-एसपी ने परखी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध सकाहा मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंचे। इसी अवसर पर जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सकाहा मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन-अर्चन एवं जलाभिषेक किया तथा जनपदवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।पूजन के उपरांत दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, साफ-सफाई तथा पुलिस बल की तैनाती का निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी अनुनय झा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिर परिसर और कांवड़ मार्गों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध रहें तथा विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और कानून-व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह तैयार रहे और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से भी संवाद किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। प्रशासन एवं पुलिस के अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर सकाहा मंदिर में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही और भगवान भोलेनाथ के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।

महत्वपूर्ण ख़बर

सेऊटा प्रवासी संकट के बाद स्पेन बनाएगा 500 मीटर समुद्री बैरियर

- सेऊटा। मोरक्को से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के प्रवेश के बाद स्पेन ने उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेऊटा की समुद्री सीमा को सुरक्षित करने के लिए नया कदम उठाने का फैसला किया है। स्पेन सरकार ने घोषणा की है कि वह सेऊटा और मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर करीब 500 मीटर लंबा तैरता हुआ बैरियर लगाएगा। यह व्यवस्था प्रवासियों के अवैध प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। हाल ही में सेऊटा में बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने के बाद हालात बिगड़ गए थे। कई लोग समुद्र के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हुई घटनाओं में 67 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार, कुछ लोगों की मौत डूबने से हुई, जबकि कुछ लोग सीमा पर लगे अवरोध को पार करने की कोशिश के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सेऊटा संकट को लेकर यूरोपीय स्तर पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सीमा प्रबंधन को लेकर स्पेन के खिलाफ की जा रही आलोचनाएं गलत धारणाओं और राजनीतिक हितों से प्रभावित हैं।

रेल की रफ्तार बनी उम्मीद की धड़कन

वंदे भारत से अहमदाबाद पहुंचा जीवंत हृदय

अहमदाबाद। भारतीय रेल ने एक बार फिर मानवता की सेवा और जीवन बचाने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जीवंत हृदय के त्वरित परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 02 अगस्त 2026 को ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रलझगांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा अंकलेश्वर से अहमदाबाद तक जीवंत हृदय का सफलतापूर्वक परिवहन किया गया।

इस अवसर पर पहली बार अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर मुंबई सेंट्रलझगांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को विशेष ठहराव प्रदान किया गया, जिससे समय पर जीवंत हृदय को कोच संख्या ई-01 में सुरक्षित चढ़ाया गया। यह जीवंत हृदय अंकलेश्वर स्थित श्रीमती जयाबेन मोदी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से अहमदाबाद लाया गया। अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं.1 पर रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों एवं आरपीएफ एवं राज्य पुलिस के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अत्यंत कम समय में यू.एन. मेहता हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया।

इस हृदय का प्रत्यारोपण यू.एन. मेहताइंस्टीट्यूट ऑफकार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद की विशेषज्ञ चिकित्सकीय टीम द्वारा किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले तीन दिनों में यह दूसरा अवसर है, जब जीवंत हृदय के त्वरित एवं सुरक्षित परिवहन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का उपयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय रेल की आधुनिक, तेज एवं समयनिष्ठ सेवाएं अब केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

हृदय प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में अंगदान से प्रत्यारोपण तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सकीय दृष्टि से डोनर हृदय को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्यारोपित करना आवश्यक होता है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी उच्च गति एवं समयबद्ध रेल सेवा डोनर अंगों के शीघ्र परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर मरीजों को नया जीवन देने का माध्यम बन रही है। पश्चिम रेलवे ने इस संवेदनशील अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित अस्पतालों, राज्य पुलिस, चिकित्सा टीमों तथा रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय सुनिश्चित किया। भारतीय रेल भविष्य में भी ऐसे मानवीय एवं जीवन रक्षक अभियानों में हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली के बाद अब झारखंड में जंतर-मंतर जैसी लामबंदी

रांची। दिल्ली में भले ही छात्र आंदोलन शांत हो गया हो, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का गुस्सा अब जंतर-मंतर जैसी लामबंदी का रूप ले चुका है। कचहरी चौक स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भारी संख्या में छात्र-छात्राएं एकजुट हो रहे हैं।

जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले जारी इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सोनम वांगचुक के अनशन की तर्ज पर अब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

रविवार को दिनभर चले प्रदर्शन के बाद शाम को बड़ी संख्या में छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में मशालें थामे और शरीर पर बैनर-पोस्टर चिपकाए हुए थे। पूरे रास्ते छात्रों ने परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। छात्रों का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।

छात्रों का अनिश्चितकालीन अनशन और मशाल जुलूस

छात्रों की मुख्य मांग है कि जिन जेएसएससी परीक्षाओं पर अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उन्हें तत्काल रद्द किया जाए। इसके अलावा टीडीपीएल कंपनी, अभय तिवारी और विवादित एजेंसियों से जुड़े परीक्षा मामलों की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सत्याग्रह के नौवें दिन अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि विवादित 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र हितों को लेकर राज्य सरकार की मंशा में खोट है। देवेंद्र ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह सत्याग्रह और भूख हड़ताल जारी रहेगी।

जैश के निशाने पर बंगाल के सीएम: शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ी, क्यों बदला पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल?

कोलकाता। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से खतरे और एसटीएफ द्वारा संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लीक हुए शेड्यूल और पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब उनके लिए बुलेटप्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया है।

पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित खतरे के इनपुट के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मुख्यमंत्री के लिए बुलेटप्रूफ वाहन के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता।

एसटीएफ ने इस मामले में पूर्व बर्धमान जिले के बर्धमान शहर से हमीम मंडल को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसकी कथित सहयोगी अर्पिता सरकार को भी हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, शुरूआती जांच में दोनों के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास से मुख्यमंत्री के दैनिक कार्यक्रम और यात्रा मार्ग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी बरामद हुई है। फिलहाल एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि यह जानकारी उनके पास कैसे पहुंची और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के काफिले में बुलेटप्रूफ वाहन पहले से शामिल था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी आमतौर पर लोगों से सीधे संपर्क बनाए रखने के लिए सामान्य वाहन से यात्रा करना पसंद करते थे। हालांकि, ताजा सुरक्षा इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें केवल बुलेटप्रूफ वाहन से यात्रा करने की सलाह दी है। रविवार शाम को कांथी स्थित अपने पैतृक आवास से कोलकाता लौटते समय उन्होंने इसी वाहन का इस्तेमाल किया।

पूर्व भाजपा सांसद रेबती त्रिपुरा ने संभाली शिक्षक की जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रेबती त्रिपुरा ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हुए अपने पुराने पेशे शिक्षण के क्षेत्र में वापसी कर ली है।

त्रिपुरा के धलाई जिले के एक सुदूर गांव के निवासी रेबती त्रिपुरा ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के बाद वर्ष 2001 में अगरतला के महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल से बतौर शिक्षक अपने करियर की शुरूआत की थी। इसके बाद वर्ष 2014 में वे भाजपा में शामिल हुए और 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी त्रिपुरा संसदीय सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। राजनीति के बाद फिर से शिक्षक बने रेबती त्रिपुरा का कहना है कि अपने मूल पेशे में लौटकर उन्हें न केवल एक नया उद्देश्य मिला है, बल्कि राजनीतिक जीवन में आए ठहराव के बाद भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।

पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पूर्वी त्रिपुरा सीट से त्रिपुरा राजपरिवार की सदस्य और टिपरा मोथा प्रमुख की बहन कृति देवी देबबर्मन को मैदान में उतारा था, जिसके बाद से रेबती त्रिपुरा का राजनीतिक करियर एक तरह से थम सा गया था। हालांकि वे प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य बने रहे, लेकिन पिछले दो वर्षों से पार्टी की गतिविधियों में उनकी सक्रियता न के बराबर थी। हाल ही में घोषित भाजपा पदाधिकारियों की सूची में भी जगह न मिलने के बाद उन्होंने अपने मूल पेशे में लौटने का मन बनाया और 20 जुलाई को स्कूल में दोबारा कार्यभार संभाल लिया।

राजनीति के बाद फिर ब्लैकबोर्ड का सहारा

पूर्व सांसद का कहना है कि पिछले ढाई वर्षों से कोर कमेटी सदस्य के रूप में उनके पास कोई विशेष काम नहीं था। खाली बैठने के बजाय उन्होंने सरकारी स्कूल में स्नातकोत्तर शिक्षक की नौकरी फिर से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाने से उन्हें सहज महसूस हो रहा है और इस नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 50,000 रुपये मासिक पेंशन सहित अन्य लाभ भी सुनिश्चित होंगे, जो एक अच्छी-खासी आर्थिक सुरक्षा है। यदि भविष्य में मन नहीं लगा तो वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी विचार कर सकते हैं। उधर, स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक टीटू साहा ने बताया कि दोबारा कार्यभार संभालने के बाद से रेबती त्रिपुरा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

29 किमी लंबे दानापुर-फतुहा सेक्शन पर 976 करोड़ की लागत से बिछेगा मल्टीट्रैक

रेलवे को यात्री और माल ढुलाई से जुड़ी सेवाओं में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद

नई दिल्ली। भारतीय रेल ने बिहार में रेल क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर-फतुहा सेक्शन पर 976 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीट्रैक बिछाने की मंजूरी दे दी है।

इस प्रोजेक्ट से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे बिजी सेक्शन में से एक दानापुर-फतुहा सेक्शन पर ट्रेनों का लोड कम होगा, जिससे यात्री और माल ढुलाई से जुड़ी रेल सेवाओं में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, कि इस मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट में 3 घटक शामिल हैं। दानापुर और पटना के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। राजेंद्र नगर और पटना साहिब के बीच तीसरी, पटना साहिब और फतुहा के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। इन एक्स्ट्रा लाइनों से पटना क्षेत्र में ट्रेनों की लेट-लतीफी कम होगी और समय की पाबंदी में सुधार होगा। बता दें देश के सबसे अहम रेल कॉरिडोर में शामिल दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर बिहार के कई जिलों से होकर गुजरता है। ये एक बेहद बिजी रेल कॉरिडोर है, लिहाजा इस कॉरिडोर पर ट्रेनों की आवाजाही लगातार चलती रहती है। ऐसे में कई जगहों पर लाइन की कमी के कारण ट्रेनों को सिग्नल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक्स्ट्रा लाइन बिछाने से न तो ट्रेनों का सिग्नल का इंतजार करना पड़ेगा और न ही ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंचने में लेट होंगी। इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा।

रिपोर्ट में रेलवे मुताबिक प्रोजेक्ट के पहले साल में रोजाना 22 एक्स्ट्रा पैसेंजर ट्रेनें और 18 एक्स्ट्रा मालगाड़ियां चल सकेंगी। इससे हर साल 52 लाख टन एक्स्ट्रा माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट दिल्ली, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना, किउल, भागलपुर, खन्ना और हावड़ा रूट पर चौगुनी रेल सुविधा शुरू करने की पहल का हिस्सा है। ये रूट भारतीय रेलवे के ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। मजबूत किया गया ये सेक्शन बक्सर जिले के चौसा में बनने वाले 2120 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए भी बहुत अहम है, जो भारी मात्रा में कच्चे माल की रेल ढुलाई पर निर्भर करेगा।

आठवें वेतन आयोग की कवायद: कर्मचारियों-पेंशनर्स से लेंगे सुझाव

नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन में बदलाव और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आयोग क्या सिफारिश करेगा, इस पर सबकी नजर है। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिए गए आयोग ने, जिसके लगभग आधे हिस्से का समय पूरा हो चुका है, अब अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके संगठनों से सुझाव जुटाने की कवायद तेज कर दी है।

आयोग की इन बैठकों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव सिफारिशों को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनमें रक्षा क्षेत्र और भारतीय रेलवे के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। रेलवे कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों को करीब से समझने के लिए आयोग सेंट्रल रेलवे जोन के तहत आने वाले रेलवे प्रतिष्ठानों का भी दौरा करने की तैयारी में है, हालांकि मुंबई दौरे की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2026 के दौरान कई राज्यों में बैठकें और दौरे करने के बाद, आयोग का अगस्त और सितंबर के लिए भी कार्यक्रम तय हो चुका है। दिल्ली में आयोग 7 और 10 अगस्त 2026 को केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों, महासंघों और यूनियनों से बातचीत करेगा। इसके बाद आयोग 7 और 8 सितंबर 2026 को चेन्नई पहुंचेगा, जहाँ तमिलनाडु के संगठन और कर्मचारी प्रतिनिधि अपने सुझाव रखेंगे। 9 सितंबर 2026 को आयोग पुडुचेरी का दौरा करेगा। फिर 16 से 18 सितंबर 2026 तक आयोग चंडीगढ़ में रहेगा, जहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। इन बैठकों में शामिल होने के इच्छुक संगठनों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन करना होगा।

संभावना है कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप देगा। इसके बाद केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर उन्हें लागू करने को लेकर अंतिम फैसला लेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का आधिकारिक गठन किया गया। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसमें से जुलाई 2026 के मध्य तक आठ महीने से ज्यादा पूरे हो चुके हैं।

नौसेना के लिए 14 नई पनडुब्बियों की खरीद करेगा अमेरिका

वॉशिंगटन। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने वैश्विक रक्षा रणनीतियों को बदल दिया है। दुनिया के प्रमुख देश अपनी सेनाओं को आधुनिक हथियारों, मिसाइल प्रणालियों और अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने में तेजी दिखा रहे हैं। अमेरिका ने हाल के दिनों में रक्षा क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे वैश्विक हथियार बाजार और सैन्य संतुलन पर असर पड़ने की संभावना है। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन के लिए करीब 59 अरब डॉलर के रक्षा अनुबंध को मंजूरी दी है।

नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा से तनाव, कई जिलों में अब भी कर्फ्यू

नई दिल्ली। नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई प्रभावित जिलों में प्रशासन ने कर्फ्यू और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रखी है। स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा से लगे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। हिंसा की शुरूआत 26 जुलाई को नेपाल के सुनसरी जिले से हुई थी। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ विवाद जल्द ही सांप्रदायिक तनाव में बदल गया और देखते ही देखते कई अन्य इलाकों तक फैल गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। इसके बाद हिंसा कोशी और मधेश प्रांत के कई हिस्सों तक पहुंच गई, जो भारत के बिहार राज्य से सटे हुए हैं।

प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। कई जगहों पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि किसी भी नई हिंसक घटना को रोका जा सके। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हालात धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने में अभी समय लग सकता है।हिंसा भड़कने के चार दिन बाद, 30 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने देशवासियों के नाम संदेश जारी कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सभी समुदायों से संयम बरतने और अफवाहों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने भी लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विवाद की जड़ धार्मिक जुलूस और तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर पैदा हुई। सावन माह के दौरान आयोजित होने वाले ह्यबोल बम उत्सवह्न में बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु कोशी बैराज से पवित्र जल लेकर कप्तानगंज चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक झड़पों में बदल गया। प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है और शांति बहाली के प्रयास जारी हैं।

ताजा खबर

संक्षिप्त

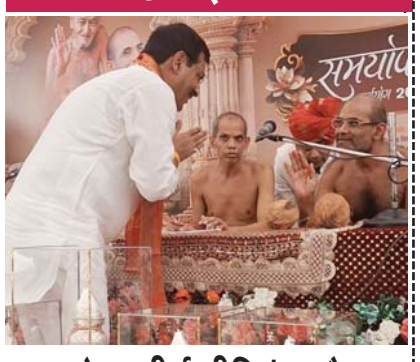

नवोदय तीर्थ श्रीदिगंबर जैन आदिशवर धाम, मालवीय रोड मंदिर में वर्षायोग कलश स्थापना

रायपुर। नवोदय तीर्थ श्री दिगंबर जैन आदिशवर धाम, मालवीय रोड दिगंबर जैन मंदिर में वर्षायोग कलश स्थापना के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के अध्यक्ष केदार गुप्ता ने संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्या सागर महाराज जी के सुशिष्य 108 श्री आगम सागर जी महाराज मुनि संघ का श्री फल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

100 सप्ताह तक चलेगा जन-जागरूकता अभियान

रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में प्रारंभ हुए 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत राजधानी रायपुर स्थित लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन तथा विभिन्न युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करते हुए 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और यदि युवा नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता का सकारात्मक उपयोग करें, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से स्वयं नशामुक्त जीवन अपनाने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इस दिशा में जागरूक करने का आह्वान किया।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 4 परिवारों को कुल 16 लाख रूपए की मिलेगी आर्थिक सहायता'

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-6 क्रमांक-4 के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदाओं एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में जशपुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 4 प्रकरणों में प्रभावित परिजनों के लिए कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। यह सहायता राशि शासन के नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी। अपर कलेक्टर प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील कांसाबेल के ग्राम तिलंगा निवासी स्वर्गीय विकास राम, पिता स्वर्गीय मनोज साय की 27 सितंबर 2025 को तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के निकटतम वैध वारिस उनकी माता श्रीमती लीलावती भगत को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील सन्ना के ग्राम छिछली (र) निवासी स्वर्गीय बंधन राम, पिता श्री सुखू राम की 16 अगस्त 2025 को सांप काटने की वजह से मृत्यु हो गई थी।

बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और विकास की गाथा को कला के माध्यम से मिलेगी नई पहचान

कार्टून कला के माध्यम से बस्तर की सकारात्मक तस्वीर पहुंचेगी देश-दुनिया तक

'मुस्कुराता बस्तर' कार्यशाला, जगदलपुर में 03 अगस्त को होगा आयोजन

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस्तर की इसी बदलती तस्वीर, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को रचनात्मक कला के माध्यम से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 'मुस्कुराता बस्तर' कार्टून कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।छत्तीसगढ़ जनसपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका 'कार्टून वॉच' द्वारा 03 अगस्त को जगदलपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए इस विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यशाला में विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर कला की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार कला के माध्यम से समाज, संस्कृति और विकास के सकारात्मक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विजन के अनुरूप बस्तर आज अपनी नई पहचान बना रहा है। प्राकृतिक संपदा, जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और पर्यटन स्थलों से समृद्ध बस्तर विकास की नई कहानी लिख रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा और यहां की विशिष्ट लोक कला-संस्कृति इसकी पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रही है स 'मुस्कुराता बस्तर' कार्यशाला इसी सकारात्मक बदलाव को कला के माध्यम से सामने लाने का प्रयास है।

'कार्टून वॉच' के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और बस्तर की खूबियों को कार्टून कला के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री माधव जोशी और पुणे के प्रसिद्ध कैरिकेचर कलाकार श्री शुभम जिंदे लाइव डेमो के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्टून एवं कैरिकेचर निर्माण की बारीकियां सिखाएंगे।

वे विद्यार्थियों को कला के सामाजिक महत्व, रचनात्मक संभावनाओं और रोजगार के अवसरों से भी अवगत कराएंगे।

'मुस्कुराता बस्तर' कार्यशाला स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ बस्तर की सकारात्मक पहचान को देशभर में पहुंचाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर से जोड़ने का रचनात्मक माध्यम बनेगा।

प्रयास आवासीय विद्यालय के नीट क्वॉलीफाई विद्यार्थियों से किया प्रेरक संवाद

सीएम साय ने नीट क्वॉलीफाई विद्यार्थियों के साथ साझा किया भविष्य का रोडमैप

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रयास आवासीय विद्यालयों के नीट-2026 में सफल विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के गरीब एवं आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों ने नीट जैसी कठिन परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 17 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य दूरस्थ, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की इस सफलता में उनके माता-पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का समर्पण और विद्यार्थियों की कठोर मेहनत समान रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी भविष्य के डॉक्टर हैं। समाज में डॉक्टर का स्थान भगवान के बाद माना जाता है। भगवान हमें जन्म देते हैं और डॉक्टर जीवन बचाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे केवल कुशल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, व्यवहारिक और मिलनसार डॉक्टर भी बनें। उन्होंने कहा कि मरीज के साथ अच्छा व्यवहार स्वयं कई बीमारियों के उपचार का माध्यम बन जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज, प्रदेश और देश की सेवा को अपना सर्वोच्च दायित्व मानने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज शिक्षा सहित हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी संघर्षपूर्ण शिक्षा यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज विद्यार्थियों को शासन की ओर से पहले की तुलना में कहीं अधिक संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए प्रदेशभर में नालंदा परिसर संचालित किए जा रहे हैं तथा 34 नए नालंदा परिसर निर्माणाधीन हैं, जहां सातों दिन 24 घंटे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। वहां विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इसी वर्ष ट्रायबल यूथ हॉस्टल के 13 विद्यार्थियों ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य निर्माण के समय प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज निजी एवं शासकीय संस्थानों को मिलाकर 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। राज्य सरकार पांच नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कर रही है, जिससे एमबीबीएस की 250 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए देशव्यापी %नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान% का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज देशभर में करोड़ों लोगों ने नशा नहीं करने की शपथ ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह अभियान स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जो आगामी दो वर्षों तक संचालित होगा तथा इसमें माय भारत वालंटियर्स सहित बड़ी संख्या में युवा सहभागी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि यदि युवा स्वस्थ, संस्कारित, परिश्रमी और नशामुक्त रहेंगे तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव होगा। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है, अपराध को बढ़ावा देता है, पारिवारिक संबंधों को कमजोर करता है तथा पूरे परिवार को संकट में डाल देता है। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

देशभर के 25 हजार केंद्रों से एक करोड़ से अधिक युवाओं ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ

रायपुर. भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत (MY Bharat) द्वारा देशव्यापी नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। देशभर के लगभग 25 हजार केंद्रों पर एक साथ आयोजित इस अभियान में एक करोड़ से अधिक युवाओं ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। कार्यक्रम में MY Bharat के स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), युवा क्लबों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 100 सप्ताह तक संचालित होने वाले नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार देशभर में जनजागरूकता, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिटनेस गतिविधियां, योग एवं ध्यान, सामुदायिक सहभागिता तथा अन्य रचनात्मक आयोजनों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा।

जशपुर जिले में अभियान के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, घोलेंग में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों एवं युवाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन देखा और सुना। विद्यालय के प्राचार्य श्री दुर्गेश पाठक ने युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा सभी उपस्थित विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में युवाओं ने नशे के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने तथा स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। अभियान के माध्यम से युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

अग्रवाल समाज की भव्य कांवड़ यात्रा संपन्न 500 से ज्यादा शिवभक्त हुए शामिल

रायपुर। अग्रवाल सभा रायपुर के सान्निध्य में अग्रवाल युवा मंडल, अग्रवाल युवती मंडल और अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा रविवार को श्रद्धा, उत्साह और भक्तिमय वातावरण के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दिव्य यात्रा में 500 से अधिक शिवभक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को कांवड़ भेंट कर एवं भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर किया। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित एवं अनुशासित यात्रा की कामना की। अग्रवाल युवा मंडल के अध्यक्ष सीएस सौरभ अग्रवाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की अभूतपूर्व सहभागिता ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।

युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया, जिससे संपूर्ण वातावरण हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। यात्रा का मुख्य आकर्षण रायपुर की प्रसिद्ध शिव तांडव टोली रही, जिसने अपने मनमोहक एवं ऊर्जावान तांडव नृत्य की प्रस्तुति से सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। डमरू की गूंज, शिव

भजनों एवं तांडव नृत्य ने पूरी यात्रा को शिवमय बना दिया और मार्गभर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। अग्रवाल युवती मंडल की अध्यक्षा कंचन अग्रवाल ने आयोजन में महिलाओं एवं युवतियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संस्कार, सेवा एवं एकता की भावना को और मजबूत करते हैं। अग्रवाल युवा मंडल के महामंत्री वेदांत अग्रवाल ने बताया कि यात्रा का संचालन पूरी व्यवस्था एवं अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। सभी स्वयंसेवकों एवं समितियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रही। हरीश केड़िया एवं मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में अग्रवाल युवा मंडल एवं अग्रवाल युवती मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने यात्रा की संपूर्ण व्यवस्थाओं का सफल संचालन किया। सभी कार्यकर्ताओं ने कई दिनों की मेहनत एवं समर्पण से इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

602 करोड़ की पाराडोल-नागपुर रोड नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए टेंडर जारी

एमसीबी जिले की रेल कनेक्टिविटी होगी और मजबूत

रायपुर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने पाराडोल से नागपुर रोड स्टेशन तक नई ब्रॉडगेज सिंगल रेल लाइन बिछाने तथा मौजूदा बोरीडांड्डूचिरमिरी लाइन के स्लूइंग कार्य के लिए ई-निविदा (ई-टेंडर) आमंत्रित किया है। ईपीसी मोड पर होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ?601.90 करोड़ है, और इसे दो वर्ष (730 दिन) में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना उस मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले से जुड़ी है। लंबे समय से इस अंचल के लोग बेहतर रेल सुविधा की मांग करते रहे हैं। नई लाइन बनने से चिरमिरी और आसपास के क्षेत्रों की रेल पहुंच और सुगम होगी, जिससे यात्रियों के साथ-

साथ इस कोयला-समृद्ध क्षेत्र के औद्योगिक और व्यापारिक आवागमन को भी नई गति मिलेगी। परियोजना के दायरे में केवल पटरी बिछाना ही नहीं, बल्कि बड़े पुल, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी), एक वायाडक्ट पुल, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली, ऑप्टिकल फाइबर केबल और विद्युतीकरण जैसे अनेक आधुनिक कार्य भी शामिल हैं। नई चिरमिरी स्टेशन, पारादोल जंक्शन तथा नागपुर रोड स्टेशन से जुड़े निर्माण कार्य भी इसी परियोजना का हिस्सा हैं, जिससे पूरा रेल खंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

क्या है परियोजना

यह कार्य पाराडोल टेकऑफ पॉइंट (किलोमीटर 947.257) से नागपुर रोड स्टेशन (किलोमीटर 964.820) तक नई ब्रॉडगेज सिंगल लाइन के निर्माण से संबंधित है। इसके साथ ही मौजूदा बोरीडांड्डूचिरमिरी लाइन का किलोमीटर 946.640 से 947.257 के बीच स्लूइंग (लाइन को नई दिशा में जोड़ने) का कार्य भी शामिल है। नई लाइन की कुल लंबाई करीब साढ़े सत्रह किलोमीटर होगी।

क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार, इस नई लाइन के बनने से चिरमिरी और एमसीबी जिले की देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी। कोयला और खनिज परिवहन को नई राह मिलेगी, जिससे स्थानीय उद्योगों और व्यापार को बल मिलेगा। निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और यातायात सुगम होने से आम लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बेहतर रेल सुविधा क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देगी। मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस परियोजना को क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है और क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया गया है कि रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। क्षेत्र के लोगों में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह है। लंबे समय से लंबित रेल विस्तार की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में चिरमिरी अंचल की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा।

समन्वित प्रयासों से नए कानूनों और डिजिटल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ बनेगा देश का अग्रणी राज्य: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

नए आपराधिक कानूनों ने न्याय व्यवस्था में लाया ऐतिहासिक परिवर्तन: मुख्यमंत्री साय

स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला

रायपुर. वर्तमान समय की आवश्यकताओं और बदलती चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए आपराधिक कानून भारत की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन के वाहक बने हैं। इन कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को त्वरित, पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रणालियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को न्याय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाकर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और जवाबदेह

बनाया गया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों की मूल भावना नागरिक-केंद्रित न्याय व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले और अपराधी कानून के शिकंजे से बच न सके। उन्होंने कहा कि पुराने कानून ऐसे समय में बने थे, जब डिजिटल तकनीक, सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान का अस्तित्व नहीं था। आज अपराधों की प्रकृति बदल चुकी है और तकनीक न्याय व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। नए कानूनों ने डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा वैज्ञानिक फॉरेंसिक जांच को विधिक मान्यता देकर अपराध अनुसंधान और अभियोजन को नई मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की शाखा प्रारंभ होने से अपराध अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। ई-साक्ष्य जैसी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित संरक्षण और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से न्याय प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और प्रभावी हुई है। पहले समन की तामील में कई दिन लग जाते थे, जबकि अब ई-समन के माध्यम से सूचना तत्काल संबंधित व्यक्ति तक पहुंच रही है और उसकी डिजिटल ट्रैकिंग भी संभव हो गई है। न्याय श्रुति जैसी व्यवस्था न्यायालयीन कार्यवाही के सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के साथ-साथ ऑनलाइन एवं हाइब्रिड सुनवाई को भी अधिक सक्षम बना रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से देशभर के पुलिस थाने डिजिटल रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं। इससे अपराधियों का रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध हो जाता है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं तथा राज्य में अब तक 1 लाख 97 हजार 547 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी हैं।

एक हजार से ज्यादा दिव्यांगों को मिलेगी मशीन

रायपुर. रायपुर में सोमवार 3 अगस्त को दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला प्रशासन की ओर से सुबह 10 बजे बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में चयनित दिव्यांगों को उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने जिले के करीब 1006 दिव्यांगजनों का चयन किया है। इन्हें ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, हियरिंग एड समेत अन्य सहायक उपकरण दिए जाएंगे।

इनसे दिव्यांगजनों के चलने-फिरने और रोजमर्रा के काम आसान होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे चयनित हितग्राहियों का सहायक उपकरण वितरित करेंगे। जिला प्रशासन के प्रोजेक्ट सहारा के तहत यह पहल दिव्यांगजनों को जरूरत के मुताबिक मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। इस मौके पर जिला प्रशासन के नवाचारों की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं प्रोजेक्ट वंदन के तहत हाल ही में सेवानिवृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों को पीपीओ और सेवानिवृत्ति से जुड़े दस्तावेज सौंपे जाएंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के कुछ हितग्राहियों का सम्मान भी किया जाएगा। अगर किसी दिव्यांगजन का चयन हुआ है, तो उन्हें तय समय पर आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचना होगा। जिला प्रशासन के अनुसार, उपकरणों का वितरण हितग्राहियों की जरूरत के अनुसार किया जाएगा।

हो गया आधिकारिक ऐलान, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत, ग्लास्गो में सौंपा गया झंडा

ग्लास्गो। ग्लास्गो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खत्म हो गया है. इसी के साथ इस बात का आधिकारिक ऐलान हो गया कि साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन भारत में होने वाला है.

क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान स्कॉटलैंड ने कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन भारत को सौंप दिया, जिसके साथ ही ये ऑफिशियल हो गया कि अगली बार ये इवेंट भारत की धरती पर होगा. बता दें, ग्लास्गो में हुए इवेंट में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया और 39 मेडल्स के साथ मेडल टैली में नंबर-4 पर रहते हुए इवेंट खत्म किया.

भारत में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन भारत में होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में भारत की ओर से गोल्ड मेडल विजेता मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई. सेरेमनी की शुरूआत कॉमनवेल्थ गेम्स के ध्वज की पूरे स्टेडियम में सांकेतिक यात्रा के साथ हुई. स्कॉटलैंड और भारत के ध्वजवाहकों की अगुवाई में जुलूस

निकला और गेम्स का आधिकारिक ध्वज उतारा गया. इसके बाद ग्लास्गो की लॉर्ड प्रोवोस्ट जैकलीन मैकलारेन ने यह ध्वज क्रमशः कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड की उपाध्यक्ष सुसान जैक्सन, स्कॉटिश नेटबॉल खिलाड़ी एमिली निकोल, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे, दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और अंत में गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपा. इसी औपचारिक ध्वज हस्तांतरण के साथ स्कॉटलैंड ने आधिकारिक रूप से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को सौंप दी.

2010 में भारत में हुआ था आयोजन

ये पहली बार नहीं होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में होगा. इससे पहले 2010 में भी इस इवेंट का आयोजन भारत में हुआ था. जिसके मुकाबले देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था. 71 राष्ट्रमंडल देश और क्षेत्रों के 6,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है. कुल 21 खेलों की 272 स्पधाएं आयोजित हुईं. भारत ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य सहित 101 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया.

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीते 39 मेडल्स

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल के 122 खिलाड़ी ग्लासगो पहुंचे थे, जिसमें से 38 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. भारतीय एथलीट्स ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते. एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा. वह एक ही राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रैक एंड फील्ड में एक से अधिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने. वहीं, मुक्केबाजी में पहली बार भारत ने 7 गोल्ड मेडल को अपने नाम किया. जबकि 3 सिल्वर मेडल जीते. यानी बॉक्सिंग इवेंट में भारत ने कुल 10 मेडल अपने नाम किए. जूडो प्रतियोगिता में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीते. इसमें अस्मिता डे (महिला 48 किग्रा) और हर्ष सिंह (पुरुष 60 किग्रा) ने स्वर्ण पदक हासिल किए.

मेडल टैली में किस नंबर पर है भारत?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा. भारत के खाते में 39 मेडल्स हो गए हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. वहीं, टैली में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 65 गोल्ड, 41 सिल्वर, 52 ब्रॉन्ज सहित कुल 158 मेडल हैं. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड काबिज है, जिसके पास 26 गोल्ड, 41 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज सहित 102 मेडल हैं.

4 छक्के, 9 चौके... वैभव सूर्यवंशी ने पिछली फर्स्ट क्लास पारी में मचाया था तहलका

67 गेंदों में जड़ दिए थे इतने रन

नई दिल्ली। दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए टीमौं के ऐलान का सिलसिला जारी है. 23 अगस्त से शुरू होने वाले इस घरेलू टूनार्मेंट में वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उपकप्तान नियुक्त किया है. वैभव अभी 15 साल के हैं.

ऐसे में उन्हें उपकप्तान बनाए जाने पर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताई. वहीं, ईस्ट जोन का कप्तान ईशान किशन को बनाया गया है. 23 अगस्त को ईस्ट जोन की टीम अपना पहला मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. आइए इससे पहले आपको बताते हैं कि पिछली बार जब वैभव सूर्यवंशी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, तब कैसा प्रदर्शन किया था.

पिछली बार फर्स्ट क्लास में कैसा रहा था वैभव का प्रदर्शन?

भारतीय क्रिकेट के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पिछली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रणजी

ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते नजर आए थे. मेघालय के खिलाफ खेले गए उस मैच में वैभव ने शानदार बल्लेबाजी की और 67 गेंद पर 93 रनों की पारी खेली. वैभव ने अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए थे. हालांकि, मेघालय और बिहार के बीच खेला गया, वो मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैसा है वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कुछ खास नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 8 मैच ही खेले हैं. सूर्यवंशी ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसकी 12 पारियों में उन्होंने 17.25 के औसत और 90 की स्ट्राइक रेट से 207 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया है. उनके बल्ले से 29 चौके और 6 छक्के निकले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 2 कैच भी लपके हैं.

वैभव को उपकप्तान बनाने के फैसले पर आया बयान

वैभव सूर्यवंशी को जब ईस्ट जोन का उपकप्तान नियुक्त किया गया, तो बवाल मच गया और इस फैसले पर आपत्ति जताई गई. हालांकि, फिर ओडिशा के पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रबंजन मलिक वैभव के बचाव में उतरे.

क्रिकबज से बातचीत में मलिक ने चयन समिति की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा, 'वह कप्तान नहीं बने हैं सिर्फ उप-कप्तान बनाए गए हैं. कप्तान ईशान किशन हैं और वह एक विकेटकीपर भी हैं इसलिए मैच के दौरान मैदान पर वे ही पूरी तरह सक्रिय रहेंगे. ऐसा नहीं है कि वैभव दिनभर कप्तानी करने वाले हैं. वैभव सूर्यवंशी समय के साथ और मैच्योर हो रहे हैं. उन्हें जिम्मेदारी देने से उनका कॉन्फिडेंस और निखरेगा.

श्रीलंका दौरे से पहले भारत को बड़ा झटका

जसप्रीत बुमराह स्क्वाड से बाहर, जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को मिला मौका

नई दिल्ली। श्रीलंका दौरे से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं. वो टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज थे, जो अहम मौकों पर विकेट लेने और शानदार यॉर्कर्स के लिए जाने जाते थे. अब उनकी कमी टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ खलने वाली है. बुमराह को जब श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्ट किया गया था, तब भी उनकी फिटनेस पर सवाल थे. क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे.

जसप्रीत बुमराह अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. ऐसे में मैच फिटनेस नहीं होने के चलते उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के स्क्वाड से अपना स्थान गंवाना पड़ा है.आपको बता दें कि, जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान

बाएं घुटने में लगी चोट से अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. पुरुषों की सिलेक्शन कमिटी ने बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया है.

श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आकिब नबी को टीम में स्थान दिया गया है. जम्मू और कश्मीर के इस तेज गेंदबाज को पहली बार सीनियर नेशनल टीम में शामिल किया गया है. ये उनका मेडन कॉल है. नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में 104 विकेट लिए, जिसमें 2025-26 कैंपेन में 60 विकेट शामिल हैं. उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन के लिए बाद उनके लगातार टीम में शामिल होने की मांग की जा रही थी.

आकिब नबी ने इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2026 खेला था. इसके साथ ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जम्मू और कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई. वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया अ टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट लिए थे. अब वो भारत की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए धमाल मचाते हुए नजर आएंगे.

स्थानीय टूनार्मेंट में अभिषेक शर्मा ने उड़ाया गर्दा, जड़ा दोहरा शतक

नई दिल्ली। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अमृतसर के गांधी ग्राउंड में खेले गए पंजाब इंटर-जिला पुरुष सीनियर वनडे टूनार्मेंट के एक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक ने 91 गेंदों पर 233 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनके इस दोहरे शतक की बदौलत अमृतसर ने तरनतारन के खिलाफ 220 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की।

महिला पहलवानों के शोषण मामले में बृजभूषण शरण बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्रक्क के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर को भी बरी किया गया है। फैसले से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो कोर्ट कहेगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा

लगाए गए यौन शोषण के आरोपों ने खेल जगत में भूचाल ला दिया था। यह मामला जनवरी 2023 में तब प्रकाश में आया जब कई शीर्ष महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाने की मांग की। पहलवानों का आरोप था कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। इन आरोपों में भारतीय कुश्ती महासंघ के कुछ कोचों की संलिप्तता की बात भी कही गई थी। इस गंभीर मामले को लेकर महिला खिलाड़ियों ने आवाज उठाई और न्याय की गुहार लगाई।

मध्य पूर्व के तनाव से उबरा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 500 का उछाल, निफ्टी 24,550 के पार

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार मध्य पूर्व के तनाव से उबरने लगा है. पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार ग्रीन जोन में बंद हुआ तो इस सप्ताह की शुरूआत भी बाजार के लिए शानदार रही. सोमवार (3 अगस्त) को शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुला. इस दौरान बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला.

सप्ताह के पहले दिन ग्रीन जोन में शेयर बाजार

सोमवार के शुरूआती कारोबार में बाजार मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिखा. शुरूआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (इरए) का सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा के उछाल के साथ 78,600 पर पहुंच गया. जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ठरए) का निफ्टी50 160 अंकों की बढ़त के साथ 24,500 के स्तर पर पहुंच गया. बता दें कि पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में निफ्टी 24,467 के हाई पर कारोबार करता दिखा था. जबकि बैंक निफ्टी अभी भी 57,500 के स्तर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है.

कैसी रही आज बाजार की शुरूआत?

बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले रुकने के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई,

जिससे भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स- सेंसेक्स और निफ्टी में आज मजबूती देखने को मिल रही है. सोमवार को 30 शेयरों वाला इरए सेंसेक्स 788.7 अंक या 1.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,883.34 पर खुला, जबकि निफ्टी 189.1 अंक बढ़कर 24,572.70 पर ओपन हुआ. पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 78,094.64 पर और निफ्टी 50 24,383.60 पर बंद हुआ था. इसी तरह, शुरूआती कारोबार में ब्रॉडर इंडेक्स भी बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे. जहां इरए मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स 123.12 अंक ऊपर था, वहीं बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स 33.45 अंक या 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,837.07 पर ट्रेड करता दिखा. सोमवार के शुरूआती कारोबार में मार्केट का रुख सकारात्मक रहा. ठरए पर 2,288 शेयरों में बढ़त और 458 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 99 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

गिफ्ट निफ्टी ने क्या दिया संकेत?

निफ्टी50 के शुरूआती इंडिकेटर, गिफ्ट निफ्टी ने आज सकारात्मक शुरूआत का संकेत दिया था. यह पिछले बंद भाव 24,448 के मुकाबले 51 अंक की बढ़त के साथ 24,499 पर खुला. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी जारी रखी और 31 जुलाई, 2026 को 277.48 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. इसी तरह, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी खरीदारी की और 2,260.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीद डाले.

शेयर बाजार में कैसे लौटी तेजी?

बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में अचानक लौटी ये तेजी मिडिल ईस्ट में कम हो रहे तनाव का नतीजा है. अमेरिका ने पिछले कई दिनों से ईरान पर हमला नहीं किया. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत शुरू होने की भी बात कही है. इसके साथ ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है. जिससे भारतीय शेयर बाजार को सपोर्ट मिल रहा है. इसके साथ ही कई घरेलू और ग्लोबल फैक्टर भारतीय इक्विटी की चाल पर असर डाल रहे हैं, जिससे निवेशकों के लिए यह समय काफी अहम हो गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी का नतीजा, कंपनियों की कमाई, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और अहम आर्थिक आंकड़े बाजार की उम्मीदों को तय करते दिख रहे हैं. जबकि कच्चे तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल तनाव भी बाहरी तौर पर बाजार के लिए काफी अहम बने हुए हैं. कुछ चुनिंदा कंपनियों की मजबूत कमाई और विदेशी निवेशकों की नई खरीदारी ने हाल की उठा-पटक के बाद बाजार के मूड को बेहतर बनाने में मदद की है.

भारत ने 10 हजार करोड़ के विदेशी निवेश को मंजूरी दी, इसमें चीन का हिस्सा सिर्फ एक करोड़

नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में चीन से आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का केवल एक प्रस्ताव मंजूर किया, जिसकी कुल राशि एक करोड़ रुपये थी। वहीं, हांगकांग से आए 13 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जिनका कुल मूल्य 610.42 करोड़ रहा।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान सरकार ने 63 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनसे कुल निवेश 10,292.67 करोड़ रुपये (करीब 1.18 अरब डॉलर) रहा। मूल्य के लिहाज से सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक रहा। उसके पांच प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनकी कुल राशि 3,259.88 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2024-25 में भी भारत ने 28.71 करोड़ रुपये के सिर्फ एक

चीनी एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच भारत में आए कुल एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 0.32% रही। इस अवधि में चीन से कुल 2.51 अरब डॉलर (करीब 16,162 करोड़ रुपये) का निवेश आया और वह सूची में 23वें स्थान पर रहा।

हांगकांग की ड्रैगन पर कड़ा पहरा

भारत ने 2020 में गलवां घाटी में भारत-चीन सैन्य संघर्ष के बाद जारी प्रेस नोट-3 प्रणाली के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चीन सहित भारत की सीमाओं से लगे देशों से आने वाले निवेश के नियम कड़े कर दिए थे। चीन के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से आने वाले निवेश के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। इससे पहले ऐसे कई निवेश विभागीय या राज्य स्तर पर मंजूर कर लिए जाते थे। सरकार का उद्देश्य था कि महामारी के दौरान वित्तीय संकट झेल रही भारतीय कंपनियों का सस्ते मूल्य पर अधिग्रहण न हो सके। हिस्सेदारी 0.62% रही। वह 4.91 अरब डॉलर (करीब 31,220 करोड़ रुपये) के साथ 15वें स्थान पर था।

बाजार की तेजी का फायदा उठाने की ताक में रिटेल निवेशक, उधार लेकर निवेश

नई दिल्ली। भारतीय रिटेल निवेशक बाजार में अपनी जेब से ज्यादा उधार के पैसे से दांव खेल रहे हैं। रेटिंग एजेंसी केयरएज के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जून महीने में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ) के तहत निवेशकों का बकाया बढ़कर रिकॉर्ड 1.36 लाख करोड़ रुपये के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। पिछले साल की तुलना में इसमें 57.6% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

चिंता की बात यह है कि एक तरफ जहां उधार लेकर शेयर खरीदने की होड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ कैश मार्केट की रफ्तार की औसत दैनिक ट्रेडिंग में जून में 6.7 फीसदी की गिरावट देखी गई है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर वैश्विक तनाव या मुनाफावसूली के कारण बाजार में अचानक गिरावट आती है, तो इस 1.36 लाख करोड़ रुपये के उधारी वाले दांव का क्या होगा? अगर आपके पास शेयर खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं है, और आपका ब्रोकर आपसे केवल 20 या 30 फीसदी पैसा लेकर बाकी रकम खुद लगाकर शेयर खरीदवा देता है, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति

■ भोपाल। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि ह्लनशा मुक्त युवा ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे प्रबल शक्ति हैं। भारत की वास्तविक सामर्थ्य उसकी युवा जनशक्ति में निहित है, और यदि यह शक्ति नशा रूपी दलदल में उलझती है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव केवल एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित न रहकर संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध करता है।" पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

जनकल्याण शिविरों में खसरा-खतौनी, नामांतरण और सीमांकन के लिए 1.11 लाख से ज्यादा आवेदन आए

इंदौर। सरकार जनकल्याण शिविरों को आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बता रही है, लेकिन इन शिविरों में आए आवेदनों का विश्लेषण प्रशासनिक व्यवस्था की एक अलग तस्वीर भी सामने लाता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शिविरों में सबसे अधिक मांग राजस्व विभाग की सेवाओं की रही। सबसे ज्यादा आवेदन चालू खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि, चालू नक्शा, नामांतरण और सीमांकन जैसे कार्यों के लिए आए। प्रदेश में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत आज भी जमीन से जुड़े दस्तावेज और रिकार्ड हैं। आंकड़ों के अनुसार, खसरा-खतौनी, चालू नक्शे, नामांतरण, सीमांकन के लिए ही 1.11 लाख से अधिक आवेदन आए। यह संख्या किसी भी अन्य सेवा की तुलना में कहीं अधिक है।

प्रमाणपत्रों की भी बड़ी मांग

राजस्व सेवाओं के बाद सबसे अधिक मांग विभिन्न प्रमाणपत्रों की रही। स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र के लिए 8,451, आय प्रमाणपत्र के लिए 6,679, अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाणपत्र के लिए 1,675 तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के जाति प्रमाणपत्र के लिए 1,314 आवेदन दर्ज हुए। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं, प्रवेश प्रक्रियाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रमाणपत्रों की जरूरत लगातार बनी हुई है।

स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाएं पीछे

दिलचस्प तथ्य यह है कि जिन योजनाओं को सरकार सबसे अधिक प्रचारित करती है, उनके लिए आवेदन अपेक्षाकृत कम रहे। आयुष्मान भारत योजना के लिए 840, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 575, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 558 और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 315 आवेदन दर्ज किए गए।

यह आए आवेदन

- खसरा-खतौनी की प्रति : 56,917
- आवेदन चालू नक्शा : 48,172 आवेदन
- निवासी प्रमाणपत्र : 8,451 आवेदन
- आय प्रमाणपत्र : 6,679 आवेदन
- अविवादित नामांतरण : 3,349 आवेदन
- सीमांकन : 2,848 आवेदन
- आयुष्मान भारत योजना : 840 आवेदन
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन : 575 आवेदन

जनकल्याण शिविरों के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में आम नागरिक की पहली प्राथमिकता अभी भी जमीन के रिकार्ड, नामांतरण, सीमांकन और जरूरी प्रमाणपत्र हैं। यह भी संकेत मिलता है कि राजस्व और प्रमाणपत्र संबंधी सेवाओं की नियमित व्यवस्था में ऐसी बाधाएं हैं, जिनके कारण लोगों को विशेष शिविरों का सहारा लेना पड़ रहा है। यदि से सेवाएं समयबद्ध और सहज उपलब्ध हों, तो ऐसे शिविरों में इन सेवाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने की आवश्यकता शायद न पड़े।

नशा मुक्त युवा शक्ति ही विकसित भारत का आधार है : उप मुख्यमंत्री

भोपाल। देश की युवा शक्ति को नशे से बचाकर राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ह्यनशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियानह्ल का शुभारंभ किया। अभियान अगले 100 सप्ताह तक जन-आंदोलन के रूप में चलेगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माय भारत और एनएसएस स्वयंसेवकों ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि युवा ऊर्जा ही भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को नशे से बचाना आवश्यक है। जब देश का युवा संकल्प लेता है तो असंभव को भी संभव कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जन-जन का आंदोलन है। अगले 100 सप्ताह तक स्कूल, कॉलेज, सामाजिक एवं युवा संगठन इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने माय भारत, एनएसएस और युवा संगठनों से अभियान के अग्रदूत बनने का आह्वान करते हुए कहा कि नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को अलग-थलग करने के बजाय उनका हाथ पकड़कर मुख्यधारा में वापस लाना होगा। परिवार, शिक्षण संस्थान, नागरिक समाज और सामाजिक-आध्यात्मिक संगठनों के सामूहिक प्रयास से ही नशा मुक्त भारत का संकल्प साकार होगा।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर एमपी ट्रांसको के सब-स्टेशन में हुआ सामूहिक पौध-रोपण

भोपाल। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के 400 केवी सब-स्टेशन ताजपुर उज्जैन में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता संवर्धन एवं प्रकृति को हरा-भरा बनाए रखने का संकल्प लिया गया। परिसर में लगभग 100 पौधे रोपे गए तथा उनकी नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प भी सभी कार्मिकों द्वारा लिया गया। कार्यक्रम मे अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल सक्सेना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि सतत जिम्मेदारी है। सभी ने अधिकाधिक पौध-रोपण करने तथा रोपे गए पौधों को वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने का संकल्प लिया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

भोपाल। मिसरोद थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और बाद में शादी से इनकार करने पर जबरन कीटनाशक पिलाकर जान लेने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

जबरन पिलाया इल्लीमार कीटनाशक

पीड़िता का आरोप है कि जब भी

वह शादी की बात करती, आरोपी टाल देता था। 30 जुलाई को दोबारा शादी का दबाव बनाने पर वह भड़क गया और युवती के मुंह में इल्लीमार कीटनाशक उड़ेल दिया। युवती ने तत्काल उल्टी कर दी, जिससे उसकी जान बच गई।

मध्यप्रदेश एसटीएसएफ की बड़ी कार्रवाई—तेंदुआ शिकार गिरोह का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार

भोपाल। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने एक संगठित अंतर्राज्यीय तेंदुआ शिकार एवं वन्यजीव अंग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएसएफ की कार्रवाई में 7 आरोपियों को श्योपुर-मुरैना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। मामले की छानबीन में जुटे एसटीएसएफ ने 23 जुलाई 2026 को आगरा में वन विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में 4 कथित वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 तेंदुओं की खालें तथा दूसरे वन्यजीव अवयव बरामद किए। प्रारंभिक जांच में इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार मध्यप्रदेश से जुड़े पाए गए। इसके बाद एसटीएसएफ ने विशेष जांच दल गठित कर आगरा तथा मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

30 जुलाई को एसटीएसएफ, कूनो वन्यजीव वनमंडल, श्योपुर वनमंडल और मुरैना वनमंडल की संयुक्त टीमों ने आरोपियों की निशानदेही पर श्योपुर और मुरैना जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान तेंदुओं की बड़ी मात्रा में हड्डियां और अन्य अवशेष बरामद किए गए। इस मामले में 2 वन अपराध प्रकरण दर्ज किए गये हैं।

10 तेंदुओं के अवशेष बरामद, कूनो समेत कई वन क्षेत्रों में शिकार की पुष्टि

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 10 तेंदुओं के शिकार की बात स्वीकार की। जांच में सामने आया कि इनमें से 6 तेंदुओं का शिकार कूनो वन्यजीव वनमंडल, दो श्योपुर वनमंडल तथा दो चंबल अभयारण्य (मुरैना वनमंडल) में किया गया था। आरोपियों से शिकार में प्रयुक्त लेग-होल्ड ट्रैप (फंदे) भी बरामद किए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि गिरोह संगठित तरीके से वन्यजीव अपराधों में संलिप्त था।

एसटीएसएफ एसटीएसएफ ने इकराम पुत्र मनीराम आदिवासी, लज्जाराम पुत्र विद्या उर्फ पन्नानाथ, गोपाल पुत्र कारू आदिवासी, महेश पुत्र जरदान आदिवासी, प्रकाश पुत्र होतम आदिवासी, हुब्बा पुत्र दीवान आदिवासी (सभी निवासी ग्राम झार बरोदा, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर) तथा गब्बर पुत्र सरूपा, निवासी ग्राम हंसई, जिला मुरैना (जिसे आगरा न्यायालय की अभिरक्षा से गिरफ्तार किया गया) को गिरफ्तार गिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को एसटीएसएफ के लिए अधिकृत विशेष न्यायालय, शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में रिमांड की कार्रवाई एवं विस्तृत विवेचना जारी है। यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि श्योपुर-विजयपुर और कूनो परिक्षेत्र शिकार की कई घटनाएं में सामने आई हैं। यही क्षेत्र कुनो राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जहां देश की महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट चीता' योजना के अंतर्गत अफ्रीकी चीतों का पुनर्वास किया गया है। पिछले चार वर्षों में कूनो वैश्विक स्तर पर वन्यजीव संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है।

छतरपुर के डायल-112 हीरोज

भोपाल। छतरपुर जिले के थाना बमनौरा क्षेत्र में डायल-112 जवानों की संवेदनशीलता, तत्परता एवं मानवीय कार्यवाही से घर से लापता होकर जंगल की ओर चले गए मानसिक रूप से अस्वस्थ 25 वर्षीय युवक को सुरक्षित खोजकर उसके परिजनों से मिलाया गया। समय पर की गई इस कार्रवाई से युवक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी। 01 अगस्त को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बमनौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामटोरिया निवासी मानसिक रूप से अस्वस्थ 25 वर्षीय युवक घर से कहीं चला गया है।

प्रदेश का एक गाँव ऐसा जो बना खेती का मिनी हॉलैंड

भोपाल। कभी पारंपरिक खेती और मौसम की अनिश्चितता से जूझने वाले धार जिले के बदनावर विकासखंड के ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी हॉलैंड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्राम रूपाखेड़ा में किसान पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी, व्हाइट डेजी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन कर देशभर में आज आधुनिक उद्यानिकी और संरक्षित खेती की सफलता की मिसाल बनकर उभरा है।

लगभग 1930 की आबादी और 391 परिवारों वाले रूपाखेड़ा में एक दशक पहले अधिकांश किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे। मौसम की मार, सीमित आय और बढ़ती खेती लागत के कारण किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं। ऐसे समय में उद्यानिकी विभाग ने किसानों को संरक्षित खेती की तकनीक से परिचित कराया। पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस के माध्यम से खेती, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी

ने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़ने का अवसर दिया।

रूपाखेड़ा में करीब 1,44,407 वर्गमीटर क्षेत्र में 44 पॉलीहाउस संचालित हैं। यहां उच्च गुणवत्ता वाले फूलों की व्यावसायिक खेती की जा रही है। इसके साथ ही लगभग 42,000 वर्गमीटर क्षेत्र में 13 शेडनेट हाउस निर्मित हैं, जहां उन्नत किस्मों की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। नियंत्रित वातावरण में फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ किसानों को बाजार में अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। रूपाखेड़ा की इस सफलता में भारत सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। योजना के तहत पॉलीहाउस निर्माण पर प्रति इकाई 19 लाख रुपये तक और शेडनेट हाउस निर्माण पर 14.20 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान किसानों के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में मददगार बना है। संरक्षित खेती ने केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पानी की बचत, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, कीट एवं रोग नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। आधुनिक पैकिंग और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों को अपने उत्पाद का अधिक लाभकारी मूल्य मिल रहा है।

ज्ञान, संस्कार और कौशल से आत्मनिर्भर बनेगी प्रदेश की नई पीढ़ी

वर्ष 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व करेंगे आज के विद्यार्थी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैरसिया में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण केवल नए विद्यालय भवन का शुभारंभ नहीं, बल्कि क्षेत्र में शिक्षा के नए युग और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुरूआत है। यह विद्यालय विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें ज्ञान, संस्कार, आत्मविश्वास और कौशल से संपन्न बनाकर जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को बैरसिया में सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यालय परिसर का अवलोकन किया और विद्यार्थियों को नवीन सर्वसुविधायुक्त विद्यालय की शुभकामनाएं दीं। करीब 35 एकड़ क्षेत्र में निर्मित शासकीय सांदीपनि ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय की लागत 50 करोड़ 74 लाख है। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में पौध-रोपण भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता-पिता बच्चों को जीवन देते हैं, लेकिन विद्यालय और गुरु उनके व्यक्तित्व को सही आकार देकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार अच्छे विद्यालय और योग्य शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारकर उन्हें समाज और राष्ट्र की अमूल्य संपदा बनाते हैं। विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण, अनुशासन, संस्कार और जीवन-दृष्टि के विकास का प्रमुख केंद्र होते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत की पहचान सदियों से ज्ञान, शिक्षा और गुरु-शिष्य परंपरा से रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना है। भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। इसी गौरवशाली परंपरा को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। पढ़-लिखकर अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी बनने के साथ आधुनिक किसान, सफल उद्यमी, कुशल व्यापारी तथा जिम्मेदार नागरिक भी बना जा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप क्षेत्र चुनकर उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। वे जिस भी क्षेत्र में जाएं, पूरी लगन, ईमानदारी और परिश्रम के साथ कार्य करते हुए श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी शिक्षा को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में सक्रिय भागीदार बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्यालय में अर्जित ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

देश के लिए, परिवार के लिए और खुद अपने लिए नशे से हमेशा रहें दूर : प्रधानमंत्री श्री मोदी

देश के एक करोड़ से अधिक युवाओं ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली से 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प' के राष्ट्रव्यापी अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह अभियान देश के युवाओं को नशे के सेवन से दूर रहने और राष्ट्र के निर्माण में उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित करने और समाज विकास की दिशा में जन भागीदारी का आंदोलन है। इस राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का देश के सभी राज्यों में सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में देश के 24 राज्यों के राज्यपाल, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री ने वर्चुअली सहभागिता की। देश के 28 स्थानों पर अभियान के शुभारंभ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों तथा माय भारत युवा संगठन के सामूहिक एवं सक्रिय प्रयासों से चलाए जाने वाला यह अभियान अगले 100 सप्ताह तक लगातार जारी रहेगा। अभियान के तहत नागरिकों विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर उन्हें संकल्पित कराया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक रविवार को समाज सेवा और जन-जागरूकता से जुड़ी विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्रव्यापी अभियान के शुभारंभ अवसर पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी कार्यक्रम से अभियान के शुभारंभ में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां नशामुक्त भारत और नशामुक्त मध्यप्रदेश के लिए सभी को हर प्रकार के नशे से दूर रहने और नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री

श्री मोदी ने नशामुक्त युवा फार विकसित भारत अभियान कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैनिट से ही प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधन का श्रवण किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनु श्रीवास्तव, मैनिट के डायरेक्टर प्रो. मनमोहन कापसे, माय भारत युवा संगठन के राज्य निदेशक श्री मंगलराम जाखड़, आयुक्त जनसम्पर्क श्री मनीष सिंह, कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा सहित मैनिट की सभी फैकल्टीज, प्रोफेसर्स तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा साथी उपस्थित थे।

राज्य सरकारें मिशन मोड में लागू करें यह अभियान

अभियान का शुभारंभ कर नई दिल्ली से राष्ट्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह अभियान एक व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले साल काशी में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ। इसमें काशी डिक्लेरेशन के जरिए युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाने की जरूरत के रूप में जन्मा एक परोपकारी और राष्ट्र कल्याणकारी विचार अब पूरे देश के लिए एक अभियान का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि जब कोई युवा नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उससे एक सपना हार जाता है, एक परिवार हार जाता है। नशा जीवन की मुस्कान छीन लेता है। नशा पूरे व्यक्तित्व का नाश कर देता है। इसलिए हमारे युवा साथी अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और खुद अपने लिए सभी प्रकार के नशे के सेवन से दूर रहें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के सभी राज्य एवं केन्द्रित शासित प्रदेशों की सरकारों से आहवान किया कि वे इस राष्ट्रीय पुनीत अभियान को अपने-अपने राज्यों में मिशन मोड में लागू करें। अभियान के दौरान हर रविवार को सामाजिक सहभागिता से ऐसे आयोजन करें, जिसमें युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता हो और वे स्वयं नशे से दूर रहने के लिए संकल्पित होकर दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि अभियान के शुभारंभ अवसर पर ही देश के 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने माय भारत युवा संगठन के स्वैच्छिक सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि सबके प्रयासों से यह अभियान देश के घर-घर तक पहुंचेगा।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।